



बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच 150 सीटों के बंटवारे पर सहमति शेष 77 सीटों पर अगले दो-तीन दिनों में चर्चा कर लिया जाएगा अंतिम निर्णय

DBD

दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

संभावित सीट बंटवारा

- बीजेपी 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है
- एकनाथ शिंदे की शिवसेना 70 से 80 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है



एनसीपी को लेकर रुख स्पष्ट

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने कहा किमहायुति में शामिल दलों ने साफ किया है कि यदि मुंबई में एनसीपी (अजित पवार गुट) नवाब मलिक के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी उसके साथ गठबंधन नहीं करेगी।

भाजपा ने तय किया 40 सूत्री कार्यक्रम

आगामी महानगरपालिका चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए 40 सूत्री कार्यक्रम तय किया है। इस कार्यक्रम को 'मिशन महानगरपालिका' के तहत गुरुवार से पूरे राज्य में लागू किया गया।

बात बनी लेफिन...

फडणवीस और शिंदे लेंगे अंतिम निर्णय

सूत्रों के अनुसार, बची हुई सीटों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संयुक्त रूप से लेंगे और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।

BJP-शिवसेना के दावे और मतभेद

सूत्रों के अनुसार, शिंदे गुट ने 227 में से 100+ सीटों की मांग रखी है। वहीं बीजेपी ने 2017 में जीते 82 डिविजन पर अपना दावा बरकरार रखा है और उन डिविजन पर भी दावा जता रही है जहां पार्टी मतभेद के कारण हार हुई थी।

विपक्षी खेमे में भी हलचल

बीएमसी चुनाव में विपक्षी खेमे में भी स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी के मुलाकात की चर्चाएं हैं।

कांग्रेस को जोर का झटका

- प्रज्ञा सातव ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ
- एमएलसी पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी का थामा दामन
- सोलापुर जिले के पूर्व विधायक दिलीप माने भी भाजपा में शामिल



हिंगोली के विकास पर भाजपा का जोर: बावनकुले

राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रज्ञा सातव ने दो दशक से अधिक समय तक स्वर्गीय राजीव सातव के साथ सामाजिक कार्य किए हैं। वह हिंगोली के विकास के लिए भाजपा में शामिल हुई हैं।

सैकड़ों समर्थकों ने भी थामा भाजपा का दामन

प्रज्ञा सातव के साथ हिंगोली से कांग्रेस के कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हुए, जिनमें पूर्व जिला परिषद सदस्य शिवाजीराव मरके, जिला प्रवक्ता विलास गोरे, तालुका अध्यक्ष भगवत चव्हाण, पंकज जाधव और अन्य शामिल हैं।

पीएम मोदी 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित

भारत-ओमान ने ट्रेड एग्रीमेंट पर किए साइन एजेंसी नई दिल्ली



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को ओमान की दो दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से सम्मानित किया गया।

भारत-ओमान संबंधों को मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ओमान के सुल्तान हैयम बिन तारिक ने भारत-ओमान संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया।

क्या कहा प्रज्ञा सातव और दिलीप माने ने?

प्रज्ञा सातव ने कहा कि स्वर्गीय राजीव सातव ने हिंगोली जिले के विकास के लिए लगातार प्रयास किए। उनके अछूरे सपनों को पूरा करने और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विकास कार्यों में सहयोग देने के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा है।

राहुल गांधी के करीबी थे राजीव सातव

स्थानीय निकाय चुनावों के ठीक बीच में सातव के इस्तीफे को कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। प्रज्ञा सातव पहली बार 2021 में महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य चुनी गई थीं।

पति राजीव सातव के निधन के बाद प्रज्ञा सातव ने महाराष्ट्र कांग्रेस की उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। राजीव सातव की गिनती राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद साथियों में की जाती थी।

विकास के एजेंडे से प्रेरित होकर लिया फैसला: चव्हाण

प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने कहा कि प्रज्ञा सातव और दिलीप माने ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र में चल रहे विकास कार्यों में योगदान देने के उद्देश्य से भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया है।

ब्रीफ न्यूज़

शिल्पा शेठ्टी के मुंबई वाले घर इनकम टैक्स की रेंड

मुंबई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेठ्टी के मुंबई वाले घर पर छापेमारी की। उनके होटल 'बेस्टियन गार्डन सिटी' से जुड़े एक मामले के सिलसिले में छापा मारा गया।

नवी मुंबई-नागपुर फ्लाइट को हरी झंडी

नवी मुंबई। नवी मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस ने क्रिसमस के अवसर पर नवी मुंबई-नागपुर सीधी उड़ान सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है।

मुंबई हार्बर में विश्वस्तरीय मरीना को मंजूरी

887 करोड़ की परियोजना, हाइब्रिड मॉडल से होगा विकास

मुंबई/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मुंबई हार्बर में करीब 887 करोड़ रुपये की लागत से विश्वस्तरीय मरीना विकसित करने की योजना को मंजूरी दे दी है।

2,000 से अधिक रोजगार, पर्यटन को बढ़ावा

करीब 12 हेक्टेयर जल क्षेत्र में विकसित होने वाले इस मरीना में 30 मीटर तक लंबी 424 नौकाओं को खड़ा करने की क्षमता होगी।

सतारा ड्रग मामले में तीन गिरफ्तार

मुंबई। मुंबई क्राइम सेल 7 (घातकापर) ने सतारा में स्थित मेफेड्रोन निर्माण कारखाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा मंजूर

मुंबई। महाराष्ट्र के बहुचर्चित सरकारी आवास घोटाला मामले में दोषी ठहराए गए मंत्री माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा गुरुवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वीकार कर लिया।

संसदीय पैनल 1971 के बाद बांग्लादेश से सबसे बड़ी चुनौती

बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथी बढ़े, पाकिस्तान-चीन का दखल

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली विदेश मामलों की संसदीय समिति ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को भारत के लिए 1971 के बाद की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया है।

बांग्लादेश के विकास में सहयोग ही रणनीतिक हल

समिति ने कहा है कि हालात अराजकता में तो नहीं जाएंगे, लेकिन भारत को इसे बेहद सावधानी से संभालने की जरूरत है।

रिपोर्ट की बड़ी बातें...

- पूरे मामले को समझदारी और श्रेष्ठ हसीना का भारत में रहना देश की मानवीय परंपरा के मुताबिक है।
- बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ रिश्ते में बदलाव और चीन की बढ़ता असर भारत के लिए चिंता का विषय है।

पार्टी नियमों का पालन: रावसाहब दानवे

रावसाहब दानवे ने कहा कि उनकी पार्टी नियमों और अनुशासन के तहत काम करती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इससे पहले नवाब मलिक और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने जेल जाने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया था।

दो साल की सजा और गैर जमानती वारंट

गौरतलब है कि नासिक जिला सत्र न्यायालय ने सरकारी आवास घोटाला मामले में माणिकराव कोकाटे को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया था।

► वेंचर मंडोसा और तारेन मंडोसा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की

डीबीडी संवाददाता | भाईदर
राज्य में महानगरपालिका चुनावों की सरगमों के बीच कांग्रेस पार्टी में जोरदार इनकमिंग देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मीरा-भाईदर विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक और प्रभावशाली नेता गिल्बर्ट जॉन मंडोसा के पुत्र वेंचर मंडोसा और तारेन मंडोसा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

स्थानीय चुनावों में देरी पर सत्ताधारी दल पर हमला

पार्टी प्रवेश और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपकाल ने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों से राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव नहीं कराए गए। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वे चुनाव हो रहे हैं, जबकि इस दौरान महानगरपालिकाओं में सत्ताधारी दल ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया।

'50 खोके, एकदम ओके' का आरोप

प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि इस अवधि में जनता के पैसे की खुलकर लूट हुई और '50 खोके, एकदम ओके' का खेल चलता रहा। उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार के पैसे कम पड़ने लगे तो सत्ताधारी दल के लोग इस के जरिए युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रच रहे हैं।

कांग्रेस में जोरदार इनकमिंग

मीरा-भाईदर में कांग्रेस को जिताने की अपील

प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं और जनता से आह्वान किया कि वे इन सबको सबक सिखाएं और आगामी मीरा-भाईदर महानगरपालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएं।



हर्षवर्धन सपकाल की मौजूदगी में हुआ पार्टी प्रवेश

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम में भाजपा और अन्य दलों के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। सपकाल ने सभी का कांग्रेस परिवार में स्वागत करते हुए कहा कि मीरा-भाईदर में अब एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है।



नफरत की राजनीति और भ्रष्टाचार का आरोप

उन्होंने कहा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस जाति-धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर सामाजिक सीहार्द को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ताधारी दल के मंत्री और उनके रिश्तेदार भ्रष्टाचार में डूबे हैं और 'मिल बांट के खाओ' का शासन चल रहा है।

ड्रमस फैक्ट्री के मामले पर तीखा हमला

सपकाल ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सातारा स्थित खेत में ड्रमस का बड़ा कारखाना उजागर हुआ था, जहां बड़ी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते कई आरोपियों को छोड़ा गया।

राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई: मुजफ्फर हुसैन

इस मौके पर पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई जारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ियों के जरिए भाजपा चुनाव जीत रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि महायुक्ति सरकार के 24 घंटे पानी और मेट्रो जैसे वादे पूरे नहीं हुए, जबकि कांग्रेस के माध्यम से मीरा-भाईदर में वास्तविक विकास कराया जाएगा।

बच्चों को इमारत से फेंकने के आरोपी आसिफ खान बरी

डीबीडी संवाददाता | ठाणे



ठाणे जिले की एक अदालत ने फरवरी 2023 में हुई एक सनसनीखेज घटना में आरोपी आसिफ शब्बीर खान (33) को बरी कर दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। मामले के अनुसार, आरोपी पर कौसा इलाके में पांच वर्षीय सैयद जोहन हुसैन और चार वर्षीय जेनब अंसारी को एक इमारत की दूसरी मंजिल से फेंकने का आरोप लगाया गया था। इस घटना में सैयद की मौत हो गई थी, जबकि जेनब गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गई थी। इस घटना ने उस समय इलाके में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था।

बाल गवाह की गवाही पर उठे सवाल

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का अभाव था। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से एक बाल गवाह की गवाही पर आधारित था, लेकिन जिरह के दौरान उसकी गवाही असंगत पाई गई। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी संदिग्ध है और एफआईआर मनगढ़ंत प्रतीत होती है।

बचाव पक्ष की दलील और रिहाई का आदेश

अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को भी महत्व दिया कि जिस इमारत से बच्चों के गिरने की बात कही गई, उसका निर्माण अधूरा था और संभव है कि बच्चे दुर्घटनावाश गिर गए हों। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।

न्यूज ब्रीफ

एलटीटी-करमाली एक्सप्रेस का मडगांव तक विस्तार

मुंबई। रेलवे द्वारा ट्रेन संख्या 22115/22116 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-करमाली-लोकमान्य तिलक टर्मिनस साप्ताहिक एक्सप्रेस का संचालन 18 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मडगांव तक बढ़ाया गया है। ट्रेन संख्या 22115 प्रत्येक गुरुवार को 00:50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई से रवाना होकर उसी दिन 11:15 बजे मडगांव पहुंचेगी, जबकि ट्रेन संख्या 22116 प्रत्येक गुरुवार को 13:50 बजे मडगांव से प्रस्थान कर अगले दिन 00:10 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन ठाणे, पनवेल, चिपलुन, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाल और करमाली स्टेशनों पर ठहराव करेगी तथा इसकी संरचना में 1 फर्स्ट एसी, 3 एसी-2 टियर, 15 एसी-3 टियर, 1 पैंटी कार और 2 जेनरेटर कार शामिल होंगी।

मनपा ने 3,778 अनधिकृत बैनर-पोस्टर हटाए

ठाणे। मनपा क्षेत्र में नगर निगम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होते ही शहरभर में लगाए गए अनधिकृत बैनर और पोस्टर हटाने की मुहिम तेज कर दी गई है। अतिक्रमण विभाग ने 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच कुल 3,778 अवैध बैनर व पोस्टर हटाए हैं। 15 जनवरी 2026 को होने वाले मतदान के महेंदर चुनाव अधिकारी व मनपा उपायुक्त उमेश विरारी के आदेश तथा सहायक आयुक्त सोपान भाईके के मार्गदर्शन में मनपा क्षेत्र की सभी 9 प्रभाग समितियों में यह कार्यवाही लगातार जारी है।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

मुंबई। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा उनकी बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापन के अनुसार, ट्रेन संख्या 09704 बांद्रा टर्मिनस - जयपुर स्पेशल शुक्रवार, 26 दिसंबर, 2025 को बांद्रा टर्मिनस से 10:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:30 बजे जयपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09703 जयपुर - बांद्रा टर्मिनस स्पेशल गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को जयपुर से 08:10 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 07:25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरोवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रत्नाम, विक्रमगढ़ आलोट, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर एवं दुर्गापुर स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास तथा जनरल सेकेंड क्लास के कोच होंगे।

कानून व्यवस्था के लिए कोपरी पुलिस का रूट मार्च

डीबीडी संवाददाता | ठाणे

आगामी ठाणे महानगरपालिका चुनावों के महेंदर शहर में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कोपरी पुलिस स्टेशन की ओर से रूट मार्च निकाला गया। इस एहतियाती कदम का उद्देश्य नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करना और चुनावी माहौल के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकना है।

सख्त कार्यवाही की चेतावनी, नागरिकों से सहयोग की अपील



रूट मार्च में 6 पुलिस अधिकारी और 30 पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस की अनुशासित और सतर्क कार्यवाही से आम नागरिकों में भरोसा बढ़ा है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर निशिकांत विश्वकर ने कहा कि चुनाव के दौरान अफवाह फैलाने, दंगा भड़काने या कानून तोड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और भविष्य में भी ऐसे रोकथाम उपाय जारी रहेंगे। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सकें।

राशन दुकानों पर नियमों की अनदेखी

कार्यवाही के बजाय शिकायत का इंतजार

डीबीडी संवाददाता | भिवंडी

भिवंडी शहर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित सरकारी राशन दुकानों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। भिवंडी 37-एफ शिवावटप कार्यलय के अंतर्गत आने वाली सैकड़ों दुकानों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। आरोप है कि कई राशन दुकानों को अवैध रूप से किराये पर दे दिया गया है और मूल लाइसेंसधारक को जगह अन्य लोग दुकानें चला रहे हैं, जबकि निर्धारित समय पर दुकानें न खुलने और न बंद होने से लाभार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।



अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इन गंभीर अनियमितताओं की रजनीकट सावत को देने के बावजूद मौके पर निरीक्षण करने के बजाय उनसे पहले लिखित शिकायत मांगी गई। इससे विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। लाभार्थियों का आरोप है कि राशन दुकानदारों और कुछ अधिकारियों के बीच कथित साटगांठ के चलते कार्यवाही नहीं होती, जिससे शिकायतकर्ताओं को केवल कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

निरीक्षण व्यवस्था के बावजूद गड़बड़ियां जारी
जानकारी के अनुसार, भिवंडी 37-एफ कार्यलय के अंतर्गत लगभग 180 राशन दुकानों हैं, जिनकी निगरानी के लिए 10 से 11 परिया इंस्पेक्टर नियुक्त हैं। प्रत्येक इंस्पेक्टर को नियमित निरीक्षण कर कार्यवाही की जिम्मेदारी सौंपी गई है, फिर भी घटिया अनाज वितरण, नापतौल में गड़बड़ी और समय पर सामग्री उपलब्ध न होने जैसी शिकायतें लगातार मिल रही हैं।

दो कर्मचारियों को 'कर्मचारी ऑफ द मंथ' पुरस्कार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी), रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, अपने कर्मचारियों के उत्कृष्ट कार्य को निरंतर प्रोत्साहित और सम्मानित करता आ रहा है। इसी क्रम में आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई कार्यालय में आयोजित एक समारोह के दौरान अक्टूबर 2025 के लिए 'कर्मचारी ऑफ द मंथ' पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर आरती राव, कैटरिंग असिस्टेंट, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल तथा शुभम चव्हाण, सहायक स्टाफ (मानव संसाधन), आंचलिक कार्यालय मुंबई को अक्टूबर 2025 माह के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और योगदान के लिए सम्मानित किया गया। दोनों कर्मचारियों को मेरिट प्रमाण पत्र के साथ नकद पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी, पहल की जानकारी



पुरस्कार आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, मुंबई के समूह महाप्रबंधक गौरव झा द्वारा प्रदान किए गए। समारोह में अपर महाप्रबंधक (पर्यटन) हर्षवर्धन सिंह रावत, प्रबंधक (पर्यटन) सुभाष नायर तथा प्रबंधक (मानव संसाधन) नागेश चौधरी उपस्थित रहे। जनसंपर्क अधिकारी डॉ. ए.के. सिंह ने बताया कि यह कर्मचारी सम्मान पहल वर्तमान वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी, जिसके तहत अब तक आठ कर्मचारियों को सम्मानित किया जा चुका है। आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र उत्कृष्टता, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं की संस्कृति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अनधिकृत बैनर और होर्डिंग हटाने के लिए विशेष अभियान

डीबीडी संवाददाता | नवी मुंबई

नवी मुंबई महानगरपालिका की सार्वजनिक चुनाव 2025-26, 15 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। चुनाव को ध्यान में रखते हुए 15 दिसंबर से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 72 घंटे के भीतर अनधिकृत बैनर, पोस्टर, होर्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान आठ विभागीय कार्यालय क्षेत्रों में कुल 1001 अनधिकृत बैनर, 578 कटआउट/होर्डिंग, 204 पोस्टर, 120 झंडे और 84 दीवार लेखन हटाए गए। इसके साथ ही सरकारी, महापालिका, सार्वजनिक और निजी स्थानों से भी राजनीतिक सामग्री हटाई गई।

हिजाब विवाद को लेकर ठाणे में विरोध प्रदर्शन

ठाणे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद गहरा गया है। इस घटना का असर ठाणे शहर में भी देखने को मिला, जहां लब्धक फाउंडेशन की नगमा शेख के मार्गदर्शन में ठाणे जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे महिलाओं की गरिमा के खिलाफ बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि हिजाब उनके धर्म और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और सार्वजनिक मंच पर किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक है, जिसका वे कड़ा विरोध करती हैं।

मतगणना के लिए 7 रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति

पहली बार बहु-स्थानों पर होगी मतगणना

विनय दूबे | भाईदर
मीरा-भाईदर शहर में वोटों की गिनती की प्रक्रिया को सुचारू और त्वरित बनाने के उद्देश्य से इस बार मतगणना पहली बार एक साथ कई स्थानों पर कराई जाएगी। कुल 24 में से 21 प्रभागों की मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने 7 रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति की है, जो अलग-अलग केंद्रों पर गिनती की जिम्मेदारी संभालेंगे।

देरी से बचने के लिए नया प्रयोग
चुनाव प्रक्रिया में होने वाली देरी को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह नवाचार किया गया है। मीरा-भाईदर मतगणना चुनाव में यह प्रयोग पहली बार हो रहा है, जिससे वोटों की गिनती तेजी से पूरी होगी और डाले गए मतों की सही संख्या शीघ्र प्राप्त हो सकेगी। साथ ही, इस व्यवस्था से अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ भी कम होगा।

प्रत्येक अधिकारी को तीन वार्डों की जिम्मेदारी
मतगणना रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण वाले कुल 7 स्थानों पर की जाएगी। प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी को तीन वार्डों की मतगणना का प्रबंधन सौंपा गया है, जबकि शेष अतिरिक्त तीन वार्डों का प्रबंधन अन्य रिटर्निंग अधिकारियों को हस्तांतरित किया जाएगा। इस विभाजित व्यवस्था से मतगणना प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी रहने की उम्मीद है।

'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की' के जयघोष से गूँजा शहर

उल्हासनगर। उल्हासनगर-विठ्ठलवाड़ी स्टेशन के समीप केडीएमसी ग्राउंड में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के पंचम दिवस पर श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नारायणानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा कि भागवत केवल सुनने की नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने की साधना है, क्योंकि भगवान कारागृह में नहीं बल्कि भक्त के निर्मल हृदय में प्रकट होते हैं। नारायण सेवा समिति, कल्याण द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय आयोजन प्रतिदिन सायं 6 से 9 बजे तक हो रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। पंचम दिवस की कथा वैदिक मंत्रोच्चार से आरंभ हुई,

गैस सिलेंडर विस्फोट मां-पुत्र झुलसे

वसई। विरार पश्चिम स्थित पद्मावती नगर इलाके में गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे गैस सिलेंडर विस्फोट की गंभीर घटना सामने आई। गोल्डन ओक इमारत के ए विंग की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 301 में अचानक गैस रिसाव होने से जोरदार धमाका हुआ, जिसमें घर में मौजूद मां और पुत्र दोनों बुरी तरह झुलसे गए। धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के अनुसंधान प्रयासों की पहचान देवना पवार (43) और उनके बेटे सिद्धेश सुरेश पवार (19) के रूप में हुई है, जिन्हें तुरंत विरार के सजीव-विरार अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही वसई-विरार नगर निगम के दमकल विभाग और वॉलेंटियर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में लिया। दमकल विभाग ने प्रारंभिक तौर पर गैस रिसाव को आग और विस्फोट का कारण बताया है, जबकि पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

कुपोषित बच्चों की संख्या में आई कमी

बोडसर। पालघर जिले में कुपोषित बच्चों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों की तुलना में कमी आई है। कुपोषण को कम करने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए जिला परिषद और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किए गए एकीकृत उपाय प्रभावी साबित हो रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र सरकार द्वारा विकसित पोषण ट्रेकर ऐप के माध्यम से हर महीने बच्चों के वजन और लंबाई का रिकॉर्ड रखती हैं। अक्टूबर माह में जिले में एक लाख 34 हजार 362 बच्चों की लंबाई और वजन की जांच की गई। इनमें से 59 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए, जबकि 839 बच्चे मध्यम रूप से कुपोषित थे। 2017 में लिए गए आंकड़ों के अनुसार, 603 बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए, जबकि मध्यम रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या 3362 थी। हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा लागू किए गए स्वास्थ्य उपायों के कारण, कुपोषित बच्चों की संख्या में हर साल लगातार कमी देखी जा रही है।

'अजित पवार की एनसीपी से गठबंधन भाजपा से हाथ मिलाने जैसा'

संजय राउत का शरद पवार की पार्टी पर तंज

डीबीडी संवाददाता | मुंबई
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि पुणे नगर निगम चुनावों के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) से गठबंधन, भाजपा से हाथ मिलाने जैसा होगा। मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि वह शरद पवार से मुलाकात करेंगे और पुणे नगर निगम चुनाव के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच किसी भी समझौते सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।



नासिक और ठाणे में एनसीपी एसपी से गठबंधन

राउत ने कहा कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आने को लेकर सकारात्मक हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी (एसपी) नासिक और ठाणे में शिवसेना यूबीटी और मनसे के साथ गठबंधन करेगी। राज्य के 29 नगर निगमों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना एक दिन बाद होगी।

अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट

एक सवाल के जवाब में राउत ने कहा, 'अजित पवार के साथ गठबंधन करना भाजपा से हाथ मिलाने जैसा होगा। अजित पवार भाजपा के एजेंट हैं, और उनके साथ कोई भी तालमेल भाजपा को मजबूत करने जैसा होगा।' गौरतलब है कि एनसीपी

और एनसीपी एसपी, दोनों पार्टियां पुणे नगर निगम चुनाव के लिए हाथ मिलाने पर बातचीत कर रही हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाजपा और एनसीपी पुणे और पिंपरी चिंचवाड नगर निगमों में

गठबंधन नहीं करेंगे, और दोनों महायुति सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबला होगा। महायुति गठबंधन में भाजपा और एनसीपी के अलावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भी शामिल है।

फर्जी बम धमकी से मुंबई-नागपुर की अदालतों में हड़कंप

एक घंटे तक कामकाज रहा ठप

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में गुरुवार सुबह बॉम्बे उच्च न्यायालय, सत्र अदालत और दक्षिण मुंबई स्थित मझगांव व एस्प्लेनेड अदालत को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। इसके साथ ही बांद्रा और अंधेरी की दो मजिस्ट्रेट अदालतों तथा दक्षिण मुंबई के दो प्रमुख बैंकों को भी इसी तरह की धमकियां भेजी गईं।

गहन तलाशी के बाद धमकियां निकलीं फर्जी



मुंबई और नागपुर की कई अदालतों व बैंकों में सुरक्षा एजेंसियों ने गहन तलाशी अभियान चलाया। जांच के बाद सभी स्थानों पर बम की धमकियां झूठी पाई गईं और किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बम की धमकी और तलाशी अभियान के कारण

बॉम्बे हाईकोर्ट सहित कई अदालतों में लगभग एक घंटे तक अदालती कार्यवाही बाधित रही। बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन टक्कर ने बताया कि सभी कोर्ट रूम की गहन जांच के बाद दोपहर तीन बजे से सुनवाई दोबारा शुरू की गई।

नागपुर जिला न्यायालय को भी मिली धमकी

नागपुर | मुंबई के अलावा नागपुर जिला एवं सत्र न्यायालय को भी बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में स्थिति लाइंस स्थित अदालत परिसर में आरडीएक्स आधारित दो विस्फोटक उपकरण लगाए जाने का दावा किया गया था।

सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन कुछ नहीं मिला संदिग्ध
धमकी के बाद नागपुर जिला अदालत में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और बीडीडीएस कार्रवाई ने परिसर की जांच की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन बागडे ने बताया कि जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और ईमेल को फर्जी करार दिया गया।

पुलिस जांच में जुटी

लगातार मिल रही फर्जी धमकियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और साइबर सेल ईमेल भेजने वाले की पहचान और उसके पीछे की मंशा का पता लगाने में जुट गई है।

16वीं मंजिल से गिरने से बुजुर्ग की मौत

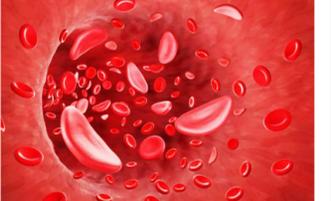


डीबीडी संवाददाता | मुंबई
विक्रोली स्थित कन्मवार नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक मल्टीस्टोरी इमारत की 16वीं मंजिल की छिड़की से गिरने से 81 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विक्रोली पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

अचानक बिगाड़ा संतुलन, अस्पताल में मृत घोषित
पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान शांताराम राणे (81) के रूप में हुई है, जो कन्मवार नगर की बिल्डिंग नंबर 135 में अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहते थे। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वह अपने कमरे में अकेले थे और छिड़की के पास खड़े होने के दौरान अचानक उनका संतुलन बिगाड़ गया, जिससे वह 16वीं मंजिल से नीचे गिर गए। आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल विक्रोली के महात्मा फुले में अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एफसीआई डेथ का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

राज्य के 21 जिलों में विशेष सिकल सेल स्क्रीनिंग अभियान

डीबीडी संवाददाता | मुंबई
राज्य के उन 21 जिलों में जहां सिकल सेल रोग के मामले अधिक हैं, वहां के प्रत्येक नागरिक को सिकल सेल जांच की जानी चाहिए। जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है कि कोई भी नागरिक सिकल सेल जांच से वंचित न रह जाए। अंबेडकर ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य में चल रहे विशेष पाश्चिमी सिकल सेल जांच अभियान के पैटर्न का पालन करने का निर्देश दिया है। जन स्वास्थ्य विभाग राज्य में 18 दिसंबर, 2025 से 15 जनवरी, 2026 तक सिकल सेल जागरूकता अभियान की तैयारी करेगा। इसके बाद, 15 से 31 जनवरी, 2026 तक 'सिकल सेल स्क्रीनिंग विशेष पखवाड़ा' चलाया जाएगा। इस स्क्रीनिंग अभियान के दौरान,



सभी एजेंसियों को प्रभावी ढंग से योजना बनानी चाहिए ताकि सिकल सेल रोग से अत्यधिक प्रभावित 21 जिलों में कोई भी नागरिक स्क्रीनिंग से वंचित न रह जाए। प्रकाश आंबेडकर ने यह भी कहा कि सिकल सेल रोग का शीघ्र निदान, उचित उपचार और रोगियों को रेफरल सेवाएं प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और राज्य में किसी भी सिकल सेल रोगी को स्क्रीनिंग से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

विकास के नाम पर हो रहा विनाश : आदित्य ठाकरे

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने अरावली पहाड़ियों और पर्यावरण को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार की योजना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। आदित्य ठाकरे ने लिखा कि पर्यावरण से जुड़े मुद्दों, खासकर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) और अरावली पहाड़ियों को लेकर लोगों का खुलकर आवाज उठा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि लोग अब पर्यावरण के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी की सरकारों को आखिर प्रकृति के हर हिस्से को नष्ट करने का यह अजीब जुनून क्यों है। उनका कहना था कि विकास के नाम पर प्रकृति को खत्म करना न सिर्फ गलत है, बल्कि देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक भी है।

'भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है अरावली'



आदित्य ठाकरे ने अरावली पहाड़ियों के महत्व को बताते हुए कहा कि यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात चार राज्यों से होकर गुजरती है। उन्होंने कहा कि अरावली पहाड़ियां देश की भौगोलिक संरचना, पर्यावरण संतुलन और जलवायु के लिए बेहद जरूरी हैं।

मध्य रेल

ई-निविदा सूचना
खुली ई-निविदा संख्या: केवायएन-एल्डी - 585 - डब्ल्यू - 754 - कॉट - आर2, दि. 15.12.2025.
कार्य का विवरण: मध्य रेलवे के मुंबई मंडल के वांगनी स्टेशन के पीएफ-1 और 2 के विस्तार के संबंध में मौजूदा ओएचई में परिवर्तन। अनुमानित लागत: ₹. 3,77,97,980.52. ईएमडी: ₹. 3,39,000/-
निविदा पत्र का शुल्क: ₹. 0/-, समाप्त अवधि: 6 महिने। ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं अवधि दि. 07.01.2026 को 11:00 बजे है। ई-निविदा की विस्तृत जानकारी रेल की अधिकारीक वेबसाइट <http://www.ireps.gov.in> पर उपलब्ध है। निविदा की जानकारी वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (क. वि.) मध्य रेल, कल्याण के सूचना पट पर उपलब्ध है।
DE-753
खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल

सोलापुर मंडल
निर्माण और आपूर्ति कार्य
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्तर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.ireps.gov.in पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। टेंडर नंबर संख्या: S U R / S R . D M M / T . N O . 96255333A, दिनांक: 17.12.2025. विवरण: आरडीएसओ स्पेसिफिकेशन नंबर एम&सी / एनडीटी / 128/ 2007 (बी-स्कैन) रिव. - IV अगस्त 2021 के अनुसार, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रेल टेस्टर जिसमें 9 प्रोब रीगन सिग्नल और रियल व स्कैन पल्स इको के साथ बी स्कैन की लगातार रिफ्लेक्शन प्रत्येक प्रोब का स्ट्रेसर और डेटा सेटअप शामिल हैं, साथ ही एसेसरीज की सूची अनुलक्ष्य - 1 (संलग्न) के अनुसार। मात्रा: 4 नं।
बयाना राशि (I N R) : ₹. 109320/-
www.ireps.gov.in पर निविदा बंद होने की तिथि और समय 08.01.2026 11:30 बजे के बाद। संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा समाप्ति की तिथि से पहले वेबसाइट पर बार-बार विजिट करते रहें ताकि इस निविदा के लिए जारी किए गए किसी भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र पर ध्यान दिया जा सके। वेबसाइट: www.ireps.gov.in
वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक मध्य रेल, सोलापुर
DE/Sur-71
खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

बीएमसी चुनाव में शिवसेना का क्रेज



227 सीटों के लिए 2700 से ज्यादा इच्छुक

डीबीडी संवाददाता | मुंबई
मुंबई महानगरपालिका चुनाव को लेकर शिवसेना की ओर से बांद्रा स्थित रंगशारदा सभागृह में इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इस दौरान बीएमसी की 227 सीटों के लिए करीब 2,700 से अधिक लोग शिवसेना से टिकट के इच्छुक नजर आए, जिससे पार्टी के प्रति बढ़ते जनविश्वास का संकेत मिला। इन साक्षात्कारों में केवल शिवसेना कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि मनसे और कांग्रेस के कई वधाधिकारी भी शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए शामिल हुए। इससे साफ हुआ कि जमीनी स्तर पर शिवसेना का जनाधार लगातार मजबूत हो रहा है।

एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर बढ़ता भरोसा

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों और जनहितकारी फैसलों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग शिवसेना से जुड़ने और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। शिवसेना के उपनेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने बताया कि बीएमसी चुनाव शिवसेना अपने सहयोगी दलों के साथ महायुति के तहत लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सहयोगी दलों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।

सीट बंटवारे पर बनी सहमति

राहुल शेवाले के अनुसार महायुति में 150 सीटों को लेकर सहमति बन चुकी है, जबकि शेष सीटों पर बातचीत जल्द पूरी कर ली जाएगी। अगले दो से तीन दिनों में तस्वीर पूरी तरह साफ होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव को लेकर जनता का भरोसा शिवसेना पर और मजबूत हुआ है, जिसका असर साक्षात्कारों में

उमड़ी भारी भीड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। राहुल शेवाले ने बताया कि मनसे, कांग्रेस सहित अन्य दलों के इच्छुक उम्मीदवार भी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कामकाज पर भरोसा जता रहे हैं। इसी विश्वास के चलते बड़ी संख्या में लोग शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।

मध्य रेल

सोलापुर मंडल
विद्युतीकरण कार्य
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्तर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए ख्याति प्राप्त, अनुभवी और लाईसेंसधारी विद्युत ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.ireps.gov.in पर ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित करते हैं। निविदा सं. सोला/क.वि./PI/2025/29R, दिनांक: 17.12.2025. कार्य का नाम: सोलापुर मंडल के अनवायर्ड पिट लाइन / साइडिंग का विद्युतीकरण का कार्य (पुनर्निविदा)। अनुमानित लागत: ₹. 1,53,83,701.79. बयाना राशि: ₹. 2,26,900/-, कार्य पुरा करने की अवधि: 12 माह। निविदा प्रस्ताव की वैधता: 60 दिन। वेबसाइट पर निविदा बंद होने की तिथि और समय: दि. 12.01.2026 को 15:00 बजे।
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर, मध्य रेल, सोलापुर
DE/Sur-70
खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

मध्य रेल

सोलापुर मंडल
निर्माण और आपूर्ति कार्य
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से मंडल स्तर कार्यालय मध्य रेलवे, सोलापुर, निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट www.ireps.gov.in पर ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित करता है। टेंडर नंबर संख्या: S U R / S R . D M M / T . N O . 96255643, दिनांक: 17.12.2025. विवरण: 60 किग्रा. रेल के लिए जॉंगलड फिश प्लेट्स का निर्माण और आपूर्ति, जो आरडीएसओ ड्राइंग नंबर टी5849 के अनुसार हों, जॉंगलड फिश प्लेट्स में शामिल हैं: (i) आरडीएसओ ड्राइंग नंबर टी-5849 के अनुसार 4 छेद वाली जॉंगलड फिश प्लेट्स 2 नग (ii) ड्राइंग नंबर टी 11513 के अनुसार बोल्ट और नट 4 नग (iii) आरडीएसओ ड्राइंग नंबर टी-10773 के अनुसार सिग्नल कॉइल स्प्रिंग वॉशर 4 नग और (iv) ड्राइंग के अनुसार स्पेशल वॉशर (50X50 मिमी.) और 10 मिमी. मोटा जिसमें 27 मिमी. व्यास का छेद हो 8 नग। विनिर्देश: फिश प्लेट्स आईआरएस टी-1-2021 (रिव. 01) (टेंडर बंद होने की तारीख तक नवीनतम बदलाव और संशोधित विनिर्देशों के साथ) के अनुरूप होनी चाहिए। मात्रा: 2584 सेट। बयाना राशि (I N R) : ₹. 267100/-
www.ireps.gov.in पर निविदा बंद होने की तिथि और समय 14.01.2026 11:30 बजे के बाद। संभावित निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा समाप्ति की तिथि से पहले वेबसाइट पर बार-बार विजिट करते रहें ताकि इस निविदा के लिए जारी किए गए किसी भी परिवर्तन/शुद्धिपत्र पर ध्यान दिया जा सके। वेबसाइट: www.ireps.gov.in
वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक मध्य रेल, सोलापुर
DE/Sur-72
खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

वसई विरार शहर महानगरपालिका

प्रभाग समिती "एफ" धानिव/पेल्हार
ता. वसई, जि. पालघर, पिन ४०१ २०८



जाहिर नोटीस

वसई विरार शहर महानगरपालिका सर्व नागरिकांना सुचित करण्यात येते की, खालील नमूद धानिव विभागातील मालमत्ता धारकांनी हस्तांतरण कामी लेखी अर्ज तसेच कागदपत्रे सादर केली आहेत. उक्त फेरफार प्रकरणी कोणतीही हरकत / तक्रार असल्यास त्यांनी कार्यालयात जाहिर नोटीस प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून ७ (सात) दिवसांच्या आत लेखी हरकत/तक्रार कागदपत्रांसह नोंदवावी सदर हरकत/तक्रार न आल्यास कार्यालय पुढील मालमत्ता हस्तांतरणाची कार्यवाही करण्यात येईल.

विभाग - धानिव

अ.क्र.	मालमत्ता क्रमांक	ज्यांच्या नावे मालमत्ता आहे त्याचे म्हणजेच विकणा-याचे किंवा करदात्याचे नाव	खरीददाराचे किंवा अभिहस्तांतरण करदात्याचे नाव
१	DN02/3103/6	आयशा खातून नियाज अहमद	तमना खातून सरफराज
२	DN04/2570/46	नासीर अली रजा शेख	मसरुफ अहमद नासुक अहमद सिद्दीकी
३	DN01/9092/1	इद्रीस अहमद मुन्ने	जुलेशा बी अख्तर हुसेन शेख
४	DN01/2910/1	सिन्दु यजकुमार चौधरी	रामानंद हंसराज यादव
५	DN04/1932	प्रभात राजदेव झा	कमलाशंकर एस. गुप्ता
६	DN04/3826/1	राममोहन जगन यादव	रश्मि सुभाष चन्द्र यादव
७	DN02/5309	दिक्षा सतोष कुमार	उमर अली
८	DN02/652/5	शेख शहाबुदीन शानउता	नुसरत जहाँ अब्दुल रशीद खान
९	DN02/239	कैलाशनाथ ईश्वरदेव मिश्रा	खोडा भगवान चौहान
१०	DN02/4149/1	सकील मो. कमरुज्जमा अब्बासी	राहुल पद्दन चौधरी
११	DN04/2410/1	गोरेलाल वचोला विश्वकर्मा	विकास सुभाष चंद्र तिवारी
१२	DN05/2162/2	साजिदा परवीन शौएव खान	अमजद हसनैन सय्यद
१३	DN03/1573	सुमन रा. मिश्रा/उस्मान अली इसहाक	विजयकुमार अमरनाथ गुप्ता
१४	DN01/3269/3	रमेश जे. गुप्ता	नीरज यादव
१५	DN02/4319/7	सकीना खातून मो. कमरुज्जमा महरूम	प्रदिप कुमार आर मिश्रा
१६	DN02/407	फजल रहीमान अन्सारी	मो. सईद मो. हदीस खान/अनिता बेगम स. खान
१७	DN01/3050	सरोज रमेश उपाध्याय	नीरज समरदेव यादव
१८	DN04/4685	मो. फिरोज अब्दुल जब्बार शेख	मोहम्मद रफतअली
१९	DN04/5584	रामप्रसाद उन्नन विश्वकर्मा	जैस मोहम्मद कलई मन्सुरी
२०	DN04/3152/3	मो. अश्रफ असलम खान	तरीकुनिसा शमसुद्दीन खान
२१	DN03/2178	अशोक दयाशंकर शुक्ला	उर्मिला समबहादुर सिंह
२२	DN03/442	ओमप्रकाश गौड व जयप्रकाश गौड	भोला शंकर सरोज / राम विलाश

सही/-
सह. आयुक्त
प्रभाग समिती (एफ) धानिव/पेल्हार
वसई विरार शहर महानगरपालिका

संपादकीय

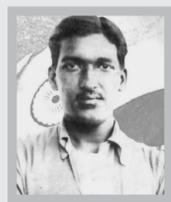
विपक्ष के निशाने पर न्यायपालिका

तमिलनाडु में जिस तरह काँग्रेसी दीपम परंपरा स्थापित करने का आदेश देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ द्रमुक और उसके सहयोगी दलों ने लामबंदी की, उससे यही संकेत मिल रहे हैं कि इस गठजोड़ के घटक बिहार के नतीजों से कोई सबक सीखने को तैयार नहीं। द्रमुक सांसद कनिमोई की अगुआई में आइएनडीआइए के 120 सांसदों द्वारा स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का नोटिस देना गठबंधन की पारंपरिक राजनीति का ही विस्तार है। गठबंधन यह पचा नहीं पा रहा कि किसी जज ने बहुसंख्यक सनानती परंपरा स्थापित करने का निर्णय दे दिया। मद्रास हाई कोर्ट की तिरुपरनकुंदम की पहली कोर्टी पर काँग्रेसी दीपम की परंपरा को स्थापित करने की मंजूरी दी, जिसे 1920 के एक विवाद के बंद कर दिया गया था। द्रमुक की अगुआई वाली तमिलनाडु सरकार ने विवाद की आशंका के बहाने स्वामीनाथन के फैसले को लागू ही नहीं होने दिया। दिलचस्प है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने इसका विरोध भी नहीं किया, बल्कि सरकार ने ही विवाद भड़काया। राज्य सरकार ने स्वामीनाथन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की, लेकिन उसे यह भी लगा कि अगर उसने जज को सबक नहीं सिखाया तो सेक्स्युलरवाद की बुनियाद पर टिकी उसकी राजनीति में दरार पड़ सकती है। जज को सबक सिखाने और न्यायपालिका पर अंकुश लगाने के द्रमुक के इस कदम में सबसे हैरतअंगेज कदम है विपक्षी गठबंधन के अन्य घटकों का बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना। लोकसभा अध्यक्ष को महाभियोग प्रस्ताव पेश करते वक्त कनिमोई के साथ कांग्रेस नेताओं और अखिलेश यादव की मौजूदगी के संकेत गहरे हैं। विपक्षी दल अल्पसंख्यक समुदाय को यह संकेत देने की कोशिश में है कि सिर्फ आइएनडीआइए ही उसके हितां के लिए किसी जज को भी निशाना बना सकता है। विपक्षी गठबंधन की कोशिश कुछ महीने बाद होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए राज्य की करीब छह प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी को लुभाना है। चूंकि द्रमुक की राजनीति के केंद्र में अल्पसंख्यकवाद का भी मंत्र रहा है, इसलिए काँग्रेसी दीपम की परंपरा को रोकने में उसे कोई हिचक नहीं हुई। इस पूरे मामले पर चर्चा से पहले जानना जरूरी है कि काँग्रेसी दीपम त्योहार है क्या? दक्षिण के दीप पर्व के रूप में विख्यात काँग्रेसी दीपम भगवान मुरुगन के सम्मान में तमिल महीने में दीप जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद को सुलझाने के लिए शिवजी स्वयं अनंत अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। उसी स्तंभ की स्मृति स्वरूप उचिपिल्लार मंदिर के पास प्राचीन दीपायुधु नामक स्तंभ के नजदीक महादीपक जलाया जाता है। तिरुपरनकुंदम की पहली पर भी इसकी परंपरा रही, लेकिन बाद में वहां मंदिर के नजदीक एक दरगाह स्थापित हो गई। दरगाह के बाद सेक्स्युलरवाद को बढ़ावा देना जरूरी था, लिहाजा दीपम की परंपरा अधिकारियों ने रोक दी। इसे ही शुरू करने को लेकर अदालती हस्तक्षेप की मांग की गई। पहले मद्रास की जिला अदालत में मामला चला और बाद में मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने पहली पर दीप जलाने की परंपरा शुरू करने का आदेश दिया। इसके बाद पहली पर तीन दिसंबर को श्रद्धालुओं का जमावड़ा होने लगा, लेकिन न्यायालय ने उन्हें रोक दिया। द्रमुक सरकार के इस दांव ने भाजपा को एक बड़ा मुद्दा दे दिया। यह पूछ रही है कि अखिर राज्य के हिंदुओं ने कौन सी गलती की है कि उन्हें दीप जलाने के अधिकार के लिए अदालत का रुख करना पड़ा और वहां से अनुकूल आदेश मिलने के बाद भी उसका पालन नहीं होने दिया गया? कोई सरकार किसी अदालती फैसले से असहमत है तो क्या उसका रास्ता महाभियोग है? एकल पीठ के विरुद्ध बड़ी पीठ का विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला था। इसके बजाय सीधे महाभियोग प्रस्ताव लाने की कोशिश से यही लगता है कि तमिलनाडु सरकार ऐसा माहौल बनाना चाहती है, जिससे आगे अदालतें उसके मनमौफिक ही फैसला दें। यह न्यायपालिका को दबाव में लेने की कोशिश है। यह कोशिश द्रमुक और उसके साथी दलों को महंगी पड़ सकती है।

शरिक्सयत

अशफाक उल्ला खां

स्वतंत्रता और साझी विरासत के पैरोकार थे अशफाक



एकता की मिसाल कायम रखने वाले प्रतीक बन आज भी प्रासंगिक हैं।

अशफाक उल्ला खां भारत मां का वो बहादुर लाल हैं जो युवाओं के हौसलों में, उत्साह में, क्रांति के नवाचार में आज भी जिब्दा हैं। देश के लिए शहादत देने वाले अशफाक उल्ला खां हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और भी प्रासंगिक हैं।

अशफाक उल्ला खां का जन्म 19 दिसंबर 1927 को हुआ था। आजादी की खुली हवा में खुल कर सांस लेना, चौगहे पर खड़े होकर बेबाकी से अपनी बात रखना, अपनी मर्जी से पूरी आस्था के साथ अपने धर्म का पालन करना, रस्में निभाना, उत्सव मनाना बेशक आज आम बात लगे लेकिन गुलामी से आजादी तक का मुश्किल सफर हमारी पीढ़ी ने नहीं जिया। हमने कितानों में पढ़ा है कुछ खास दिनों में जिया है। यह सब खुशनुमा माहौल, यह खूबसूरत विरासत जिस पर हम अपना दावा पेश करते हैं, जिसने आज चांच पर पानी की तलाश शुरू कर दी है, मंगल पर जीवन की तलाश पर लगा है, सब की सब कर्जदार है उन वीर सपूतों की जिन्होंने बिना किसी मोह माया के अपने परिवार को असुरक्षित छोड़ कर भारत की हिजाजत के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। फांसी के फंदे पर ऐसे शान से चढ़े जैसे कोई अपनी शादी में घोड़ी न चढ़े। वीरों के इस लम्बी फेहरिस्त में एक नाम भारत मां के लाल अमर शहीद अशफाक उल्ला खां का भी आता है। ईमान जिसकी दोलत पर आजाद भारत देखना जिसकी एकमात्र ख्यातिशों की मंजिल थी। 22 अक्टूबर सन 1900 ई. में उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में स्थित शहीद गढ़ में मोहम्मद शफीक उल्ला और

महसूनिशा के घर एक असाधारण प्रतिभा के धनी बालक ने जन्म लिया। बचपन से ही पढ़ने-लिखने में उस बालक का ज्यादा मन न लगा शायद छोटी उम्र में कुछ बहुत बड़ा करने का इरादा था उसका। यह वो दौर था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि अंग्रेजी हुकूमत कब तक भारतीयों को अपनी ही धरती पर गुलाम बनाकर रखेगी। देश 1857 का बसंकाक आंदोलन, अंग्रेजों की बदलती राजनीति और चालबाजी से वाकफ हो चुका था। बालक अशफाक की बचपन से पसंद तैरकी, घुड़सवारी और निशानेबाजी में थी। कविताएं लिखकर अपनी बात कहने का शौक था। कहते हैं हसरत उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखीं। जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, भारतीय राजनीति एक नए मोड़ के लिए तैयार हो रही थी तब अशफाक उल्ला खां महज 15 वर्ष के रहे होंगे। बाल्यकाल और युवा अवस्था की मध्य बेला में ही अशफाक देश में होने वाले आंदोलनों और क्रांतिकारी परिवर्तनों से प्रेरित होकर क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से बहुत प्रभावित हुए और रामप्रसाद बिस्मिल से मिलने की ख्यातिश और उनके साथ जुड़ने की जद्दोजहद में लग गए।



शालिनी सिन्हा

विश्व रिकार्ड (सबसे अधिक विविध साहित्यिक एवं पत्रकारिता रूपों वाली सबसे कम उम्र की महिला लेखिका - राष्ट्रीय रिकार्ड पर्व अनुसंधान सहायिका (केंद्रीय उपग्रह बागवानी संस्थान, लखनऊ) गेट फेकल्टी (एजाज रिच्यो कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म) स्थानीय संपादक (नॉर्थ इंडिया टाइम्स) प्रबंध अधिकारी (शहरी खेती एवम निरंतरता संस्थान) युवा लेखिका एवं आभर

8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुडुचेरी की एक युवती के पक्ष में दिया गया फैसला भारतीय न्यायशास्त्र में सामाजिक पहचान और समानता के अधिकार की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी अंतर-जातीय विवाह (जहाँ माता-पिता में से एक अनुसूचित जाति से हो) से उत्पन्न संतान ने अपने जीवन में वही सामाजिक उपेक्षा और भेदभाव झेला है जो एक दलित व्यक्ति झेलता है, तो उसे जाति प्रमाण पत्र से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह निर्णय पितृसत्तात्मक समाज की उस गहरी जड़ वाली सोच पर प्रहार करता है, जहाँ बच्चे की जाति केवल उसके पिता के वंश से निर्धारित होती है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस 'रक्त के सिद्धांत' के बजाय 'अनुभव के सिद्धांत' को प्राथमिकता दी है। यदि एक बच्चा अपनी दलित माँ के साथ ऐसे परिवेश में पला-बढ़ा है जहाँ उसे समाज के हाशिए पर रहना पड़ता है, तो उसे आरक्षण के संवैधानिक लाभों से केवल इसलिए वंचित करना कि उसके पिता सवर्ण या अन्य पिछड़ी जाति के हैं, उसके साथ घोर अन्याय होगा। यह फैसला वास्तव में संविधान के अनुच्छेद

14 और 15 की मूल भावना को सशक्त करता है, जो अवसर की समानता की बात करते हैं। यह स्वीकार करना कि भेदभाव केवल जन्म से नहीं बल्कि परवरिश और सामाजिक व्यवहार से तय होता है, आधुनिक न्यायपालिका का एक बड़ी उपलब्धि है। आरक्षण का प्राथमिक उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन ऐतिहासिक और सामाजिक अन्यायों को ठीक करना है जो एक व्यक्ति को उसकी जाति के कारण झेलने पड़े हैं। इस फैसले के माध्यम से कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि आरक्षण का लाभ 'रक्त की शुद्धता' के आधार पर नहीं, बल्कि 'सामाजिक कलंक' के आधार पर मिलना चाहिए। यदि एक बच्चा अंतर-जातीय विवाह से पैदा हुआ है लेकिन समाज ने उसे एक दलित के रूप में ही देखा और प्रताड़ित किया है, तो उसे आरक्षण से वंचित करना आरक्षण के मूल उद्देश्य—यानी सामाजिक प्रतिनिधित्व—को विफल कर देता है। यह फैसला 'जाति' को एक बंद डिब्बे के बजाय एक 'सामाजिक अनुभव' के रूप में देखने की कवाकाल करता है। दूसरी ओर, इस फैसले के कार्यान्वयन को लेकर गंभीर चिंताएं भी पैदा होती हैं। सबसे बड़ी चुनौती 'सामाजिक कट्ट' और 'भेदभाव' के स्तर को प्रमाणित करने की है। वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में राजस्व अधिकारियों के पास ऐसा कोई वस्तुनिष्ठ पैमाना नहीं है, जिससे यह मापा जा सके कि किसी व्यक्ति ने कितना भेदभाव सहन किया है। इससे जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता बढ़ेगी, जो भ्रष्टाचार और फर्जीबाड़े के द्वार खोल सकती है। इसके अलावा, आलोचकों का तर्क है कि इससे अनुसूचित जाति की मूल सूची में संख्यात्मक दबाव बढ़ेगा, जिससे उन समुदायों के हिस्से का लाभ कम हो सकता है जो सदियों से पूरी तरह से वंचित रहे हैं। कानूनी स्पष्टता के अभाव में, यह निर्णय भविष्य में विभिन्न राज्यों के नियमों के बीच विरोधाभास भी पैदा कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तकनीकी कानूनी बाधाओं के ऊपर सामाजिक सच्चाई



को तरजीह देता है। यह उन बच्चों के लिए आशा की किरण है जो अंतर-जातीय विवाहों के कारण अपनी पहचान के संकट से जूझ रहे थे। परंतु इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कितनी स्पष्टता और पारदर्शिता के साथ इसके लिए नए दिशा-निर्देश तय करती है। पहचान का आधार केवल कागजी दस्तावेज नहीं, बल्कि व्यक्ति का वास्तविक जीवन संघर्ष होना चाहिए। लेकिन इन संघर्षों को मापना और उस आधार पर उसको आरक्षण का लाभ देना एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती भी है। देखा गया है कि किसी एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिलने के बाद वह लाभ उसी पीढ़ियों में आगे बढ़ती चली जाती है। वे पीढ़ियाँ जो शसक्त हो चुकी हैं और वंचितता के प्रक्रम से मुक्त हो चुकी हैं उनको या तो स्वयं लाभ लेना छोड़ देना चाहिए, या फिर सरकार द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको हटाना जाना चाहिए, ताकि वंचित और जरूरतमंदों तक यह लाभ पहुंचा जा सके। लेकिन वास्तविकता यह है कि लाभ लेने वाला व्यक्ति लाभ छोड़ना नहीं चाहता और आरक्षण के भीतर आरक्षण का प्रावधान राजनीतिक लाभ पाने वाला चलन बन चुका है। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने 'कोटा के भीतर कोटा' या उप-वर्गीकरण को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। पुडुचेरी का यह फैसला उस बहस को और अधिक सूक्ष्म बनाता है। जब हम आरक्षण के भीतर उन लोगों की पहचान करने की बात

करते हैं जो 'सर्वाधिक पिछड़े' हैं, तो यह फैसला एक नई श्रेणी खड़ा करता है। वे बच्चे जो मिश्रित पृष्ठभूमि से हैं लेकिन दलित पहचान के साथ जी रहे हैं या जीना चाहते हैं, क्या इन्हें उन जातियों के समान माना जाए जो पीढ़ियों से अंतर्विवाही रही हैं और पूरी तरह से अलग-थलग रही हैं? या माँ के दलित पहचान को बच्चों में प्रविष्ट कर नारी को और ज्यादा सशक्त किया जाए। इस निर्णय से आरक्षण की सूची कभी स्थिर नहीं बनी रहेगी। बल्कि उसमें अब व्यक्ति की वास्तविक सामाजिक स्थिति को परखने का भी प्रावधान किया जाएगा। यदि अंतर-जातीय विवाह (विशेषकर यदि एक पक्ष संपन्न या सवर्ण वर्ग से है) से पैदा हुए बच्चों को बेहतर शिक्षा या आर्थिक संसाधन मिला हो तो क्या ऐसे में उनको अपनी अपनी माँ की जाति के आधार पर आरक्षण देना उचित होगा। ऐसे बच्चों को अनुसूचित जाति के कोटे में शामिल करना उन बच्चों के अवसरों को कम कर सकता है जिनके माता-पिता दोनों ही अशिक्षित या अत्यंत गरीब और दलित हैं। 'आरक्षण के भीतर आरक्षण' का लक्ष्य सबसे कमजोर व्यक्ति तक पहुँचना था किंतु वर्तमान समय में यह जातीय और राजनीतिक लाभ पाने का मुद्दा बन चुका है। बेहतर होता कि आरक्षण पर आरक्षण बढ़ाने की जगह शिक्षा, कौशल और रोजगार पर ध्यान दिया जाता तो आरक्षण जैसी चीजों की अवबतक जरूरत शायद खत्म हो जाती। कबतक आरक्षण के नाम पर वंचितों और बेबहाराओं को बरगलाया जाता रहेगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलेजेंस के इस युग में हम इन्हीं सब मुद्दों के बीच फंसे रहने वाले हैं? असली असमानता तो अब इस दौर में आने को तैयार बैठे हैं। अगर अब भी हम सबने शिक्षा कौशल और नई तकनीक को सीखने में पिछड़ गए तो तमाम आरक्षण भी हमारे भविष्य को नहीं सुधार सकेगा। आज एक शिक्षा, कौशल और वैज्ञानिक क्रांति की जरूरत है जो न सिर्फ असमानता खत्म करेगी बल्कि समाज की बहुत सी कुरीतियों को भी जड़ से खत्म के देगी।

जीवन मंत्र

खुद की कमियाँ निकालते हैं तो इससे आपकी सेल्फ एस्टीम प्रभावित होती है। और आपके अंदर का आत्मविश्वास कमजोर होने लगेगा।

जीवन मंत्र

हर इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। ये एक ऐसी जरूरी चीज है जिसके बल पर वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। जिस इंसान में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो ज्यादातर सक्सेस नहीं पाते। अगर आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है तो जरा इन 5 आदतों पर गौर करें। अगर ये आदतें आपकी लाइफ का हिस्सा हैं तो फौरन इन्हें दूर कर दें। तभी आत्मविश्वास बढ़ पाएगा। अगर आप खुद के बारे में हमेशा निगेटिव बातें बोलते और सोचते हैं। खुद की कमियाँ निकालते हैं तो इससे आपकी सेल्फ एस्टीम प्रभावित होती है।

सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो इन आदतों को त्याग दें

और आपके अंदर का आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। आपको खुद पर विश्वास नहीं रहता कि कोई काम आप अकेले कर सकते हैं। इसलिए सेल्फ वेल्यूएशन करने और खुद को क्रिटिसाइज करने के बीच का फर्क समझकर निगेटिव सोचना बंद करें। किसी भी काम में परफेक्शन अच्छी बात है लेकिन यहाँ परफेक्शन की चाह कई बार आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। क्योंकि जरा सी कमी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कई बार सेल्फ कॉन्फिडेंस पर निगेटिव असर पड़ता है। दूसरों से तुलना करना अगर आदत बन जाती है



तो खुद में केवल कमियाँ ही कमियाँ नजर आती हैं। जिसकी वजह से आत्मविश्वास कमजोर होता है। अगर आप लाइफ में आने वाले नए चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये आपकी ग्रोथ को रोक सकती है। क्योंकि मन में बात आती है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, जो कि पूरी तरह से कमजोर आत्मविश्वास की निशानी है। लाइफ में और अपने आसपास आपसे जुड़े लोगों के जीवन में हो रही किसी भी समस्या के लिए अगर आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर बना देती है।

जीवन ऊर्जा

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं। उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 में हुआ। उन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सदस्य, उन्होंने पहले 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया और 1991 से 1996 तक लोकसभा की सदस्य रहीं।

जीवन ऊर्जा

भ्रष्टाचार विकास और सुशासन का दुश्मन है, इससे छुटकारा पाना चाहिए। इस राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और जनता दोनों को एक साथ आना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबी, भुखमरी और कुपोषण, बीमारी और निरक्षरता को दूर करना है। सभी सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को कुशलता से लागू किया जाना चाहिए। सेवाओं के वितरण में शामिल एजेंसियों में कर्तव्य की एक मजबूत भावना होनी चाहिए और एक पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त कार्य करना

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल: जन्म 19 दिसंबर 1934

जन्म

भ्रष्टाचार विकास और सुशासन का दुश्मन है

में सुशासन की जरूरत है। वित्तीय संस्थान, कॉर्पोरेट जगत और नागरिक समाज-सभी को अपने काम में सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों को बनाए रखना चाहिए। केवल सरकार और उसके लोगों के बीच एक वास्तविक साझेदारी ही न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि सदन की मर्यादा और गरिमा हर समय बरकरार रहे। जनता के मन में संसद की छवि ऐसी होनी चाहिए, जहाँ रचनात्मक और सहयोग के माध्यम से मुद्दों को हल करने की दृष्टि से कार्यवाही, बहस और चर्चा हो।



अपने विचार

जब इंटरनेशनल स्तर पर कोई बड़ी बैठक हो तो भारत में बैठे हुए उसकी तारीख या वक्त तय नहीं हो सकता। राहुल की यह यात्रा धूमने नहीं, बल्कि जरूरी मीटिंग के लिए है और इससे भारत को फायदा ही होगा। हमारी समस्या यह है कि हमें एक्सपर्ट्स से कम सलाह मिलती है। यहाँ वकील ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। वायु प्रदूषण पर सभी कदम नाकाम रहे हैं। स्कूल बंद करने का फैसला अस्थायी नीति है, इसमें दखल नहीं दे सकते।

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

समुद्र देवता पर चलाए जाने वाला ब्रह्मास्त्र

सी ताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। रामायण: समुद्र देवता पर चलाए जाने वाला ब्रह्मास्त्र बाण भगवान राम ने कहाँ छोड़ा? रामायण में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र देवता से रास्ता मांगते हैं और उन्हें रास्ता नहीं मिलता। उस समय श्री राम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में आकर वह अपना धनुष उठाते हैं और समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने



है कि उसका संबंध रामायण काल से हो सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम ने उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य के लिए बाण चलाया था। वो जानते थे कि इसके असर से वहाँ डाकू तो मर जाएंगे लेकिन निद्रोष जीवजंतु भी मारे जाएंगे और पूरी धरती रेगिस्तान बन जाएगी। इसलिए उन्होंने यह आशीर्वाद भी दिया कि कुछ दिन बाद वहाँ सुगंधित औषधियाँ उगेंगी, वह जगह पशुओं के लिए उत्तम, फल मूल मधु से भरी होगी। कजाकिस्तान में जिस जगह पर राम का बाण गिरा वो जगह किजिलकुम मरुभूमि के नाम से जानी जाती है। यह दुनिया का 15वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। स्थानीय भाषा में किजिलकुम का मतलब लाल रेत होता है। माना जाता है कि कि ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा के असर से यहाँ की रेत लाल हो गई। किजिलकुम में कई दुर्लभ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पास में अराल सागर है जो दुनिया का इकलौता समुद्र है जो समय के साथ साथ सूख रहा है। आज यह अपने मूल आकार का मात्र 10 फीसदी बचा है। किजिलकुम का कुछ हिस्सा तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में भी है। रामेश्वरम तट से इस जगह की दूरी करीब साढ़े चार हजार किलोमीटर है।

का मन बना लेते हैं। तभी समुद्र देवता प्रकट होकर उन्हें अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं और श्री राम को बताते हैं कि वह वानरों की सहायता से समुद्र में पुल बनाकर लंका जा सकते हैं। भगवान राम समुद्र देवता की बात सुनकर उन्हें क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्रोध में निकाले गए ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं रख सकते थे। तब उन्होंने समुद्र देवता से पूछा कि अब तो ये बाण कहीं न कहीं छोड़ना ही पड़ेगा। इस पर समुद्र देवता उन्हें द्रुमकुल्य नाम के देश में बाण छोड़ने का सुझाव देते हैं। समुद्र देवता का कहना था कि द्रुमकुल्य पर भयंकर दस्यु (डाकू) रहते हैं जो उनके जल को भी दूषित करते रहे हैं। इस पर

राम ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वाल्मीकि रामायण में दिए गए वर्णन के अनुसार ब्रह्मास्त्र की गर्मी से द्रुमकुल्य के डाकू मारे गए। लेकिन इसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सारे पेड़ पौधे सूख गए और धरती जल गई। इसके कारण पूरी जगह रेगिस्तान में बदल गई और वहाँ के पेड़ मर गए। सागर भी सूख गया। यह वर्णन बेहद आश्चर्यजनक है और जिस तरह से लंका तक बनाए गए रामसेतु को भगवान राम की एतिहासिकता के सबूत के तौर पर माना जाता है उसी तरह इस घटना को भी सही माना जाता है। माना जाता है कि यह जगह आज का कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान में ऐसी ढेरों विचित्रताएँ हैं जो इशारा करती



पंडित कैलाशचंद्र शर्मा

वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक। मो. नं. 9425980556

रामेश्वरम तट से इस जगह की दूरी करीब साढ़े चार हजार किलोमीटर है।



दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हादसों का संबंध लोगों के व्यवहार से है। लोगों में कानून के प्रति न सम्मान है और न डर। लोग ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते। सुरक्षा का ख्याल नहीं रखते। इन वजहों से अधिकांश हादसे होते हैं।

रविवार को राजधानी में हुई कांग्रेस की रैली के दौरान पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने पीएम की कब्र खोदने की धमकी दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री को धमकी दिए जाने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुःखद है।

अपने विचार डीबीडी कार्यालय ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 indiangroundreport@gmail.com भेज सकते हैं।

न्यूज ग्रीफ

भड़काऊ भाषण के मामले में आजम खान बरी

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण से जुड़े एक मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। रामपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने वर्ष 2019 के मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में गुरुवार को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। यह मामला 2 अप्रैल 2019 को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान 'लाला' की ओर से रामपुर शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय, रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने कथित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। शिकायत में तत्कालीन जिलाधिकारी अंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान मंडलायुक्त, मुरादाबाद मंडल) सहित अन्य अधिकारियों पर टिप्पणी का उल्लेख किया गया था। इसी आधार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए आजम खान को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय के इस निर्णय को उनके लिए अहम कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

मिलावटखोरों पर 31.42 लाख का जुर्माना

उरई। जनपद जालौन में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई में दोषी खाद्य कारोबारियों पर 31.42 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह जानकारी कलेक्टर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने की। बैठक में बताया गया कि विशेष अभियानों के तहत लिए गए 315 खाद्य नमूनों में 68 मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। इस पर 66 बच्चों न्यायालय में दायर किए गए, जिनमें 46 मामलों में दोषियों को दंडित किया गया। दूध में मिलावट के दो मामलों में अभियुक्तों को छह-छह माह का कारावास व जुर्माना भी दिया गया। जिलाधिकारी ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ नियमित निरीक्षण और नमूना जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। दूध, सब्जी, फल, खोया, दाल और बेसन की सघन जांच पर विशेष जोर दिया गया है।

अमेठी को 550 बेड वाले मेडिकल कॉलेज की सीगात

अमेठी। जनपद अमेठी को शीघ्र ही 550 बेड की क्षमता वाला आधुनिक स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय मिलने जा रहा है। करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से तिलोई तहसील में निर्मित हो रहा यह मेडिकल कॉलेज जिले और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी स्वास्थ्य सीगात साबित होगा। फिलहाल कॉलेज से संबद्ध 200 बेड का अस्पताल संचालित है, जबकि 31 जनरल तह 300 बेड का नया अस्पताल और 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक हेडऑवर किया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग कॉलेज का निर्माण भी लगभग पूरा होने की उम्मीद है। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें स्वीकृत हैं, वहीं पैरामेडिकल के 11 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 230 सीटों पर पढ़ाई चल रही है। अस्पताल में ओपीडी और इनडोर सेवाएं नियमित हैं, जहां विभिन्न विभागों में प्रतिदिन एक हजार से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है।

27 दिन से फरार सपा के पूर्व विधायक

दीपनारायण सिंह का सरेंडर

एजेंसी | झांसी

लूट और रंगदारी के मामले में 27 दिन से फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने गुरुवार सुबह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। गरीटा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे दीपनारायण सिंह का सरेंडर उस समय हुआ, जब पुलिस को इसकी पूर्व सूचना तक नहीं थी। जानकारी के अनुसार, पूर्व विधायक अदालत खुलने से पहले ही न्यायालय परिसर में पहुंच गए थे। जैसे ही न्यायिक कार्यवाही शुरू हुई, उन्होंने सीधे न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटस मूर्ति ने सरेंडर की पुष्टि की।



पुलिस को नहीं लग सकी भनक, लूट और रंगदारी में फरार थे पूर्व विधायक

65 से अधिक मुकदमों दर्ज पूर्व विधायक के खिलाफ आपराधिक मामलों का लंबा इतिहास रहा है। विभिन्न थानों में उनके विरुद्ध करीब 65 मुकदमों दर्ज बताए जा रहे हैं। हाल ही में मोंट थाना क्षेत्र में लूट और रंगदारी का मामला दर्ज होने के बाद से पुलिस उनकी तलाश में लगातार दबिश दे रही थी।

20 करोड़ से अधिक की संपतियां कुर्क

गौरतलब है कि इससे पहले 13 दिसंबर को जिला प्रशासन और पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक की 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की तीन संपतियों को कुर्क किया था। इनमें कुरगुआजी स्थित प्लॉट, भगवंतपुरा क्षेत्र की 'मून सिटी' की भूमि और बनगुआ गांव की कृषि भूमि शामिल है। जिलाधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई थी और इससे पूर्व उनके आवास पर कुर्की का नोटिस भी चरपा किया गया था।

एसएसपी ने की सरेंडर की पुष्टि

एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि मोंट थाने में दर्ज लूट और रंगदारी के प्रकरण में पूर्व विधायक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने स्वयं न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। आगे की कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

प्रेम विवाह पर मिली अमानवीय सजा, पेड़ से बांधकर पीटा

वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस, दो आरोपी गिरफ्तार

जूता-चप्पल की माला पहनाकर सार्वजनिक रूप से किया गया अपमान



औरैया। जनपद के फर्रुद थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह करने पर एक युवक के साथ अमानवीय और शर्मनाक व्यवहार का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया और जूतों-चप्पलों की माला पहनाकर उसका सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। इटावा जनपद के भरथना क्षेत्र निवासी उषेंद्र बीएससी का छात्र है। उसने 29 नवंबर को फर्रुद थाना क्षेत्र की रहने वाली कल्पना नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था। आरोप है कि 7 दिसंबर को उषेंद्र अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके क्षेत्र पहुंचा, तभी रामपुर कुंवर गांव के कुछ युवकों ने उसे पकड़ लिया। पीड़ित के अनुसार, दीपू और भूरे नाम के युवकों ने उसे पेड़ से बांध

दिया, जबकि आलोक और राजाराम ने बांस से उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद आरोपियों ने जूतों-चप्पलों की माला पहनाकर उसका अपमान किया और पूरी घटना का वीडियो बना लिया। पीड़ित का आरोप है कि बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन थाने में उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भय और सामाजिक दबाव के चलते वह लंबे समय तक चुप रहा। हाल ही में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, जो किसी तरह उसके पिता हरिश्चंद्र तक पहुंचा। वीडियो देखने के बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक अधिषेक भारती ने बताया कि तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर फर्रुद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। वीडियो की जांच के आधार पर सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: सड़क हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन की मौत

कोहरे के कारण बकाबू ट्रक ने कार को पीछे से मारी टक्कर मुबारकपुर क्षेत्र में हुआ हादसा, चार घायल पहुंचे अस्पताल



एजेंसी | आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह पूर्वांचल

एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में पिता-पुत्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। घायलों का

जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार, मेरठ हस्ताक्षर फर्जी पाए गए। इसके आधार पर तुलसीपुर थाने में मद्रसे के प्रधानाचार्य मेराज अहमद, लिपिक अजीज अहमद अंसारी सहित अन्य के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। मामले को लेकर निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि तत्कालीन रजिस्ट्रार मद्रसा बोर्ड और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की भूमिका की विधिक जांच जारी है। तथा एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि डाली (32), अंशिका, कर्तिक (12) और चालक सत्या घायल हो गए। सूचना पर पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। सीओ सदर आस्था जायसवाल ने बताया कि मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और घटना की जांच की जा रही है।

20 हजार वेफर्स क्षमता वाली ओसैट यूनिट से यूपी बनेगा सेमीकंडक्टर हब

एजेंसी | लखनऊ

उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर उद्योग को नई रफ्तार मिलने जा रही है। एचसीएल और फॉक्सकॉन की संयुक्त ओसैट (असेंबली एवं टेस्टिंग) यूनिट के स्थापित होने से प्रदेश सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरेगा। इस अत्याधुनिक इकाई की मासिक क्षमता 20 हजार सिलिकॉन वेफर्स प्रोसेस करने की होगी, जिससे बड़े पैमाने पर चिप उत्पादन संभव हो सकेगा। करीब 3,706 करोड़ रुपये के निवेश से यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास बनने वाली यह यूनिट उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्टिंग सुविधा होगी। जनवरी के मध्य ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद परियोजना पर तेजी से काम शुरू होने की संभावना है।

डिस्प्ले ड्राइवर चिप का होगा निर्माण

इस संयंत्र में मुख्य रूप से डिस्प्ले ड्राइवर चिप का निर्माण किया जाएगा, जिनका उपयोग मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। इससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। विशेषज्ञों के अनुसार, यह परियोजना उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अहम स्थान दिलाने के साथ भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को भी मजबूती देगी।



फिर से उड़ान भरने लगी इंडिगो एयरलाइन

इंडिगो ने शुरू किया रोजाना 2,200 फ्लाइट्स का नेटवर्क

एजेंसी | नई दिल्ली

विमानन कंपनी इंडिगो ने अपने फ्लाइट नेटवर्क को पूरी तरह बहाल कर दिया है और अब रोजाना लगभग 2,200 उड़ानों का परिचालन हो रहा है। कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने गुरुवार को कहा कि एयरलाइन का फोकस अब खुद को मजबूत करने, पिछले व्यवधानों के मूल कारण का विश्लेषण करने और फिर से पूर्ण परिचालन पर लौटने पर है। एल्बर्स ने कर्मचारियों को दिए वीडियो संदेश में कहा कि

मुश्किल समय में टीम ने एकजुट होकर काम किया और नेटवर्क को धीरे-धीरे पटरी पर लाया। उन्होंने बताया कि इसके लिए निदेशक मंडल ने एक बाहरी विमानन विशेषज्ञ को भी नियुक्त किया है। एल्बर्स ने कहा, "9 दिसंबर को परिचालन में स्थिरता आई थी। आज 18 दिसंबर तक हमने 2,200 उड़ानों का नेटवर्क बहाल कर लिया है। अब हमारी प्राथमिकता एयरलाइन को मजबूत करना, मूल कारणों का विश्लेषण और फिर से वापसी करना है।"

शीतकाल में दस फीसद की कटौती



जिन्होंने व्यापक व्यवधान के दौरान जमीनी स्तर पर काम किया। इस बहाली के साथ इंडिगो ने देश के घरेलू विमानन क्षेत्र में परिचालन स्थिरता लौटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है।

मजबूत हुआ भारत-ओमान का व्यापारिक रिश्ता, समझौते पर हस्ताक्षर

भारत के विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा

मस्कट। भारत और ओमान ने गुरुवार को मस्कट में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत कपड़ा, चमड़ा, जूते-चप्पल, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, फर्नीचर, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में पूर्ण टैरिफ उन्मूलन लागू होगा, जिससे भारत के विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। गोयल ने बताया कि यह समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों, एमएसएमई, कारीगरों और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए रोजगार और अवसर बढ़ाएगा।

दो साल हुई संविदा सेवा की मियाद



समझौते के तहत संविदात्मक सेवा प्रदाताओं के लिए रहने की अवधि 90 दिन से बढ़ाकर दो साल की गई है, और आगे इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकेगा। इससे आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वास्तुकला, लेखांकन, और अन्य पेशेवर सेवाओं में भारतीय विशेषज्ञों के लिए नए अवसर खुलेंगे। गोयल ने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देगा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा और भारत के समावेशी एवं सतत विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को मजबूती देगा।

अगले माह मार्केट में आएगी निसान की एमपीवी ग्रेवाइट सात सीटर कार मार्च 2026 से देशभर के शोरूम में होगी उपलब्ध

एजेंसी | नई दिल्ली

निसान मोटर इंडिया अपनी नई कॉम्पैक्ट 7-सीटर बी-एमपीवी ग्रेवाइट जनवरी 2026 में लॉन्च करने जा रही है। मार्च 2026 से यह मॉडल देशभर के शो रूम में उपलब्ध होगा। कंपनी ने अभी इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। ग्रेवाइट निसान की भारत के लिए रीफ्रेशड और रणनीतिक प्रोडक्ट लाइन-अप का पहला मॉडल होगा। इसमें केबिन में खुलापान और क्लास-लीडिंग स्टोरेज फीचर्स दिए गए हैं। अल्ट्रा मॉड्यूलर सीटिंग के जरिए पैसेंजर और कार्गो की अलग-अलग जरूरतों के अनुसार आसानी से बदलाव किया जा सकेगा, जिससे यह रोजाना के सफर और फैमिली रोड ट्रिप के लिए उपयुक्त है।

भारतीय ग्राहकों की सुविधा का पूरा ख्याल



निसान के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स ने बताया कि ग्रेवाइट भारतीय ग्राहकों की विविध जरूरतों के अनुसार तैयार की गई है और यह कंपनी की प्रोडक्ट ऑफिसिव में दूसरा मॉडल है। कंपनी की योजना के अनुसार 2026 के मध्य में टैकॉन और 2027 की शुरुआत में 7-सीटर सी-एसयूवी भी लॉन्च होगी। ऑल न्यू ग्रेवाइट का निर्माण चेन्नई प्लॉट में किया जाएगा और यह निसान के भारतीय बाजार में नए सिरे से फोकस और ग्राहक संतुष्टि की दिशा में अहम कदम साबित होगा।

चौथे दिन निवेशकों को 79 हजार करोड़ का घाटा

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन गिरावट जारी

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद लगातार चौथे कारोबारी दिन कमजोरी के साथ बंद हुआ। शुरुआती गिरावट के बाद दिन भर लिवाली और बिकवाली के बीच खींचतान जारी रही, लेकिन अंततः बाजार लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 0.09 प्रतिशत और निफ्टी 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ सत्र का समापन करने में सफल रहे। कारोबार के दौरान कैपिटल मार्केट, मेटल और रियल्टी शेयरों में खरीदारी दिखी। कंज्यूमर ड्यूरेबल और आईटी सेक्टर भी मजबूती के साथ बंद हुए। इसके विपरीत ऑटो, बैंकिंग, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर और पीएसयू शेयरों में दबाव बना रहा। बीएसई मिडकैप

सूचकांक 0.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.28 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। बाजार में आई कमजोरी के चलते निवेशकों की संपत्ति में करीब 79 हजार करोड़ रुपये की कमी आई। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण घटकर 465.39 लाख करोड़ रुपये (अर्न्तम) रह गया, जो पिछले कारोबारी दिन 466.18 लाख करोड़ रुपये था। सेंसेक्स 77.84 अंक टूटकर 84,481.81 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मामूली 3 अंक की गिरावट के साथ 25,815.55 अंक पर उरहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 84,780.19 अंक का ऊपरी और 84,238.43 अंक का निचला स्तर छुआ।

बीएसई पर 4332 शेयरों में लेनदेन



दिन के कारोबार में बीएसई पर 4,332 शेयरों में लेनदेन हुआ, जिनमें 1,631 शेयरों में तेजी और 2,506 में गिरावट दर्ज की गई। एनएसई पर 2,812 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें 1,042 बढ़त और 1,770 गिरावट के साथ बंद हुए। दिग्गज शेयरों में इंटरनेट एंजिनिंग, टीसीएस, मैक्स हेल्थकेयर, टेक महिंद्रा और इफोसिस प्रमुख लाभ में रहे। वहीं सन फार्मा, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एशियन पेट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट में गिरावट दर्ज की गई।

लोकसभा में 'जी राम जी' विधेयक पारित

विपक्ष ने लोकतंत्र को कलंकित और संसदीय परंपराओं को तार-तार किया: शिवराज

संसद सत्र

एजेंसी | नई दिल्ली

लोकसभा ने गुरुवार को विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक को मंजूरी दे दी। विपक्ष ने विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग दोहराई, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे खारिज कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि विधेयक पर सदन में आठ घंटे से अधिक चर्चा हो चुकी है और 99 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया है। इसके बाद हंगामे के बीच अध्यक्ष ने ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा का जवाब देने को कहा। मंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सांसद अध्यक्ष के आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। कई सांसदों ने हाथों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीरें ले रखी थीं। इस दौरान कामज फाड़कर फेंके गए और कुछ सांसद लोकसभा महासचिव की मेज तक पहुंच गए।



मनरेगा के नामकरण का इतिहास गिनाया

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शुरुआत में इस योजना का नाम नरेगा था। वर्ष 2009 के आम चुनावों से पहले कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार ने मनरेगा को पूरी ताकत से लागू नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान

ने कहा कि कांग्रेस शासन में जहां 1,660 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए, वहीं मोदी सरकार में 3,210 करोड़ श्रम दिवस बनाए गए। साथ ही मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 56.73 प्रतिशत हो गई है।

शिवराज का कांग्रेस पर पलटवार

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर महात्मा गांधी के आदर्शों की "हत्या" करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बापू के आदर्शों को व्यवहार में उतार रही है। मनरेगा की जगह नए विधेयक में महात्मा गांधी का नाम हटाने के विपक्षी आरोपों को खारिज करते हुए शिवराज ने कहा कि सरकार विकसित गांधी की नींव पर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य पूरा न होने पर नई योजनाएं लाना जरूरी होता है।

KIIFB मसाला बॉन्ड केस

सीएम विजयन को राहत

ईडी नोटिस पर हाई कोर्ट की रोक

कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को केरल इंफ्रा स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) मसाला बॉन्ड मामले में सीएम पिनाराय विजयन को बड़ी राहत दी है। उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के बाद किसी भी कार्यवाही पर तीन महीने के लिए रोक लगा दी। मामले में जस्टिस वी जी अरुण ने पूर्व राज्य वित्त मंत्री थॉमस इसाक और



विजयन के मुख्य प्रधान सचिव और केआईआईएफबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के एम अब्राहम को भी अंतरिम राहत दी।

सीएम की याचिका पर उच्च न्यायालय का निर्देश

यह आदेश सीएम विजयन, इसाक और अब्राहम की ओर से दायर किए गए संयुक्त याचिका पर आया है। याचिका में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) ने (ईडी) के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। यह नोटिस मसाला बॉन्ड फंड के इस्तेमाल को लेकर जारी किया गया था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए था। कोर्ट ने कहा कि चूंकि केआईआईएफबी की याचिका पर आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए सीएम विजयन, इसाक और अब्राहम को भी इसी तरह की अंतरिम राहत के हकदार थे। मामले में कोर्ट ने संयुक्त याचिका स्वीकार कर ली और याचिका में दिए गए तर्कों पर ईडी से जवाब मांगा।

विपक्षी सांसदों का व्यवहार 'गुंडाराज' जैसा : शिवराज

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक पर चर्चा के दौरान संसद में हुए हंगामे को लेकर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों के व्यवहार को "गुंडाराज जैसा" करार दिया।

लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित होने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी

वीबी-जीरामजी विधेयक पर आपत्ति समझ से परे है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के अमर्यादित व्यवहार से लोकतंत्र को अपमानित किया गया है। कामज फाड़कर उछालना और सदन में हंगामा करना संसदीय परंपराओं को तार-तार करने जैसा है।

भ्रष्टाचार और नाम बदलने पर तंज



मनरेगा में खामियों और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए शिवराज ने कहा कि मजदूरी और सामग्री के अनुपात में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। ग्रियंका गांधी वाड़ा के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गांधी परिवार के नाम रखने की "सनक" रही है और नेहरू, इंदिरा व राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों योजनाएं और संस्थान रखे गए।

न्यूज़ ब्रीफ

जम्मू-कश्मीर में खनन परिवहन पर जीपीएस अनिवार्य

जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने खनिजों की ढुलाई पर निगरानी कड़ी करते हुए जीपीएस, आरएफआईडी और ई-वालान को अनिवार्य कर दिया है। प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सभी खनन परिवहन वाहनों को 26 जनवरी तक की समय सीमा तय की है। इसके बाद इस नियम का पालन न करने वाली पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनन विभाग के अनुसार, अब कोई भी खनिज जैसे बोट्टल, रेत, बजरी, मिट्टी, ईट आदि जीपीएस लगे वाहनों के बिना और विभाग में पंजीकृत आरएफआईडी नंबर के बिना नहीं ले जाया जा सकेगा। इसके अलावा, व्यूआर कोड या वॉटरमार्क वाला वेड ई-वालान भी अनिवार्य होगा।

पांच राज्यों से नौ साइबर जालसाज गिरफ्तार

नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली जिले के साइबर थाना पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए पांच राज्यों में एक साथ छापेमारी कर नौ साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ देशभर से गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम पोर्टल पर 286 शिकायतें दर्ज पाई गई हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों के बैंक खातों के जरिए 16 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध लेनदेन किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेक बुक, पासबुक और अन्य अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इन बेनिफिशियरी खातों के तार दुबई से जुड़े हुए हैं।

अभिनेता दिलीप का पासपोर्ट जारी करने का आदेश

2017 में जमानत की शर्त पर सरेंडर किया था पासपोर्ट

एजेंसी | कोच्चि

2017 के अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद अदालत ने अभिनेता दिलीप का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया है। एनाकुलम जिला एवं प्रधान सत्र न्यायालय के जज हनी एम. वर्गीस ने दिलीप की याचिका पर यह फैसला सुनाया। 13



दिसंबर को दायर याचिका पर पहले विशेष लोक अभियोजक ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि अभियोजन पक्ष बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करना चाहता है, लेकिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके बाद अदालत ने दिलीप का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दे दिया।

क्या है मामला ?

गौरतलब है कि 2017 में गिरफ्तारी के बाद जमानत की शर्त के तहत दिलीप ने अपना पासपोर्ट सरेंडर किया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें बिजनेस और फिल्म प्रमोशन के उद्देश्य से विदेश यात्रा की अनुमति

भी दी थी। इससे पहले कोर्ट ने दिलीप समेत चार आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर शामिल छह दोषियों को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई थी।

21 दिसम्बर को दादरा पधारंगे प.पू. श्रीमद् विजय प्रबोधचंद्र सुरेश्वरजी महाराज

दादरा। जैन समाज के परम श्रद्धेय, जीव-दया, करुणा और अहिंसा के महान उपासक 93 वर्षीय प.पू. श्रीमद् विजय प्रबोधचंद्र सुरेश्वरजी महाराज के पावन आगमन को लेकर दादरा क्षेत्र में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। गुरुवर के स्वागत को लेकर समाज के हर वर्ग में विशेष उमंग देखी जा रही है। प.पू. श्रीमद् विजय प्रबोधचंद्र सुरेश्वरजी महाराज 21 दिसम्बर को सूरत से वापी होते हुए दादरा पधारंगे। उनके आगमन को लेकर जैन समाज के साथ-साथ अन्य समाजों में भी व्यापक उत्साह है। श्रद्धालु गुरुवर के दर्शन एवं आशीर्वाद के लिए आतुर हैं।

22 दिसम्बर को जैन उपाश्रय का उद्घाटन

गुरुवर के आगमन के पश्चात 22 दिसम्बर को रत्नलीला आराधना भवन स्थित जैन उपाश्रय का भव्य उद्घाटन सम्यन् होगा। यह आयोजन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। उत्सव श्रृंखला के अंतर्गत 23 दिसम्बर को महा-भव्य पूजन का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान होंगे और क्षेत्रभर से श्रद्धालु सहभागी बनेंगे। आयोजन को लेकर समाज में खास तैयारी और उत्साह देखा जा रहा है।

पीएम आवासों की नगर पालिका ने की सघन जांच

सिलवासा। बलदेवी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बने मकानों को लेकर बुधवार शाम नगर पालिका प्रशासन ने सख्त जांच अभियान चलाया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया और लाभार्थियों में हलचल देखी गई।

नगर पालिका को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत बने कुछ मकानों का उपयोग नियमों के विपरीत किया जा रहा है। इन्हें शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर भौतिक सत्यापन शुरू किया।

मकानों का भौतिक सत्यापन और दस्तावेज जांच

जांच टीम ने आवंटित आवासों की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान लाभार्थियों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए, ताकि पात्रता और स्वामित्व से जुड़ी स्थिति स्पष्ट की जा सके। सूत्रों के अनुसार, कुछ मकानों को लेकर अनियमितता और धांधली की चर्चाएं पहले से चल रही थीं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ आवासों का उपयोग किराये पर देने या अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जो योजना के नियमों के खिलाफ है।



प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमुख नियम

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकान केवल पात्र लाभार्थी के नाम पर आवासीय उपयोग के लिए होता है। मकान को किराये पर देना या व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग करना पूर्ण तरह प्रतिबंधित है। योजना के अनुसार लाभार्थी के पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। साथ ही, आवंटित मकान का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए

ही किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का अवैध हस्तांतरण या बिक्री नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। जांच के दौरान अधिकारियों ने साफ कहा कि यदि किसी भी आवास में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित लाभार्थी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मकान का आवंटन रद्द करने की प्रक्रिया भी शामिल हो सकती है।

चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई जनवरी तक टली



एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को उस याचिका पर सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने राज्य में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई हिस्सों में नहीं की जा सकती।

18 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। चैतन्य ने घन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी है। सुनवाई की शुरुआत में चैतन्य बघेल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्य कोत और जस्टिस जॉयमलत्या बागची की बैंच के समक्ष यह कि जांच एजेंसी बार-बार किसी न किसी को गिरफ्तार करती

रहती है और जांच को लगातार जारी रखती है। कपिल सिब्बल ने कहा, यह सिलसिला नहीं चल सकता। यह सब चुन-चुनकर किया जा रहा है। एक बार उन्हें रिहा किया जाता है और फिर दूसरा वारंट जारी कर दिया जाता है। अब बिना जारी समयसीमा का वारंट जारी किया जा रहा है। एजेंसी किसी को गिरफ्तार कर लेती है और जांच चलती रहती है। कोई भी दमनकारी कदम न उठाया जाए।

पुलित्जर विजेता पत्रकार पीटर अर्नेट का निधन

लॉस एंजिल्स। अपनी जान जोखिम में डालकर युद्ध की आंखों देखी रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पीटर अर्नेट का निधन हो गया है। 'पुलित्जर पुरस्कार' से सम्मानित अर्नेट 91 वर्ष के थे। उनके बेटे एंड्रयू अर्नेट ने यह जानकारी दी। पीटर प्रोस्टेट कैन्सर से जूझ रहे थे और शनिवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अर्नेट पत्रकारिता जगत का एक बड़ा नाम रहे हैं। वर्ष 1966 में 'द एस्पिरिटेड प्रेस (एपी)' के लिए वियतनाम युद्ध की कवरेज करने पर उन्हें अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग की श्रेणी में 'पुलित्जर पुरस्कार' से नवाजा गया था। वर्ष 1962 से 1975 तक वियतनाम युद्ध की उनकी रिपोर्टिंग ने उन्हें पहचान दिलाई। हालांकि, पीटर अर्नेट को असली पहचान 1991 में मिली, जब पहले खाड़ी युद्ध के दौरान उन्होंने 'सिएनएन' के लिए युद्ध के मैदान से लाइव रिपोर्टिंग की थी।

नफरती भाषण दिया तो खैर नहीं

कर्नाटक विधानसभा से 'हेट स्पीच और हेट क्राइम्स रोकथाम विधेयक 2025' पारित

सजा में संशोधन भी मंजूर

एजेंसी | बेंगलूरु

कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को समाज में नफरत, दुश्मनी और वैमनस्य फैलाने वाली गतिविधियों पर लगातार लगे हुए हेट स्पीच और हेट क्राइम्स रोकथाम विधेयक, 2025 पारित कर दिया। विधेयक पर बेलगावी में चर्चा हुई, जिसमें गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने इसके प्रावधानों और जरूरत को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच का मतलब किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन (जीवित या मृत) के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातों का कहना, लिखना, छापना, फैलाना या उकसाना है, जिससे समाज में दुश्मनी, घृणा या वैमनस्य पैदा हो।

कानून के तहत सजा का प्रावधान

नए कानून के तहत हेट क्राइम करने वाले को कम से कम एक साल और अधिकतम सात साल की जेल, साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना होगा। अगर कोई व्यक्ति बार-बार ऐसा अपराध करता है, तो सजा और कड़ी होगी। दोहराए गए अपराध में कम से कम दो साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अधिकतम सजा को पहले प्रस्तावित 10 साल से घटाकर 7 साल किया जाए। उनका कहना था कि कानूनी ढांचे के भीतर रहते हुए सात साल की सजा पर्याप्त है। विधानसभा ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी।



'कुछ बयान सीधे तौर पर हिंसा भड़काते हैं' परमेश्वर ने कहा कि कुछ बयान सीधे तौर पर हिंसा भड़काते हैं या एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़ा और साफ कानून जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अखबारों में ऐसे बयान छापते रहें, जिनमें किसी समुदाय के खिलाफ हिंसा की बात कही जाती है।

स्मृति शोष

मूर्तियों में जान फूंकने वाले प्रख्यात मूर्तिकार राम वनजी सुतार का निधन

चिरनिद्रा में सो गए बापू को प्रेरणा मानने वाले शिल्पकार

मुंबई। 'मूर्तिकला चित्रकला जैसी नहीं होती। इसमें अक्सर बहुत ज्यादा कठोर और शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि मैं अभी लंबे समय तक काम करता रह सकता हूँ।' शिल्पकार की जीवंत मूर्ति रहे राम जी सुतार ने यह बात एक विदेशी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कही थीं। इस इंटरव्यू की तारीख खंगालें तो शायद वह 89 वर्ष के रहे होंगे। यह जीवन और जिजिविषा का सबसे सार्थक उदाहरण है, क्योंकि 89 वर्ष की अवस्था आज के समाज में संपूर्ण से अधिक की मानी जाती है, लेकिन राम सुतार ने जब गुरुवार को सुबह चिरनिद्रा को अपनाया तो वह 100 वर्ष के हो चुके थे और आप आश्चर्य करें इससे पहले ही यह बता देना जरूरी है कि अभी लगभग 20 दिन पहले ही पीएम मोदी ने गोवा में श्रीराम की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, जिसकी निर्माण और संकल्पना राम जी सुतार ने ही की थी। यानी वह निधन से ठीक पहले भी पूरी तरह न सिर्फ सक्रिय थे बल्कि अपनी शिल्प साधना भी जारी रखे हुए थे। चंबल को माता का रूप देने वाले, महात्मा गांधी की स्मृति को प्रतिमा में ढालने वाले और 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' से भारत की पहचान ऊंची करने वाले शतायु शिल्पकार राम जी सुतार, जिन्होंने 100 वर्ष की उम्र तक पत्थर, मिट्टी और धातु से संवाद नहीं छोड़ा। अब उनकी यादें स्मारकों में जीवंत रहेंगी।



कई पुरस्कारों से सम्मानित

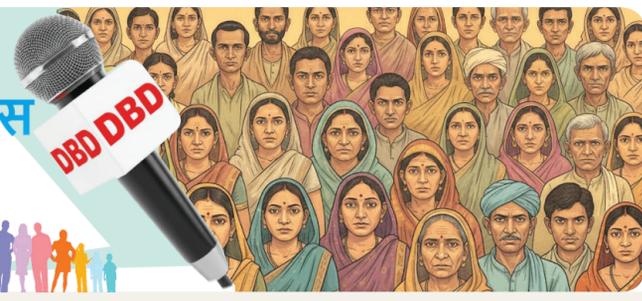
कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राम सुतार को 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार और 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2024 का महाराष्ट्र भूषण अवॉर्ड सम्मानित व्यक्ति राम सुतार के लिए घोषित किया गया।

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर अनुरोध किया था कि वरिष्ठ मूर्तिकार महाराष्ट्र भूषण राम सुतार के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे तुरंत स्वीकार कर लिया है। राम सुतार के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ नोएडा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने मूर्तिकार के बेटे को फोन कर अपनी संवेदनाएं जताते हुए उन्हें सांत्वना दी।

चंबल स्मारक पर उनके काम को काफी पहचान मिली

अपने 100 वर्ष के जीवन में तकरीबन 400 से अधिक यादगार स्मारकों के तौर पर प्रमुख शिल्पों की रचना कर चुके राम सुतार का जन्म साल 1925 में उत्तरी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता बड़ई और लोहार थे। उनके शुरुआती कामों में घर की कच्ची दीवारों पर गोबर से बनाए गए भित्तिचित्र शामिल थे। उन्होंने स्कूल की रलेट पर एक हिंदू देवी की आकृति उकेरी, जिसने मुंबई (तत्कालीन बॉम्बे) की एक कला प्रतियोगिता में पुरस्कार दिलाया। बाद के दिनों में दोस्तों की आर्थिक मदद से उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित कला विद्यालयों में से एक जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई पूरी की और एलोरा व अजंता की गुफाओं में प्राचीन हिंदू मूर्तियों के संरक्षण का काम किया। उनका बड़ा ब्रेक तब आया, जब उन्होंने उत्तरी भारत में एक बांध के पास 45 फीट ऊंची एक नदी देवी की प्रतिमा बनाने का काम महज 10,000 रुपये में स्वीकार कर लिया। बहुत कम लोगों को भरोसा था कि वह यह काम पूरा कर पाएंगे। वह अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ उस दरदरा जगह में चले गए और 1960 के शुरुआती वर्षों में 18 महीने तक एक विशाल कंกรีट के ढांचे को तैराशते रहे। इस तरह उन्हें पहली बड़ी पहचान मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध पर बनी चंबल नदी की प्रतिमा से ही मिली। एक नदी को प्रतिमा के रूप में ढालना अपने आप में दुष्कर काम था। हालांकि भारत के पौराणिक आख्यानों में नदियां अक्सर देवी के तौर पर पूजी जाती हैं और प्राचीन ग्रंथों में उनका मानवीकरण किया गया है।



कोने-कोने से...

आठवले की पार्टी ने महायुति गठबंधन में मांगी हिस्सेदारी

मुंबई। महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका में हो रहे चुनाव में रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने महायुति गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी मांगी है। आठवले की पार्टी मुंबई में 25 सीटों की डिमांड रखी है। वहीं अन्य महानगरपालिका में 7 से 10 सीटों की मांग रखी है। पार्टी ने कहा कि उन्हें गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेताओं का मानना है कि एनडीए में एक महत्वपूर्ण घटक पक्ष के रूप में उनकी भूमिका है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले केंद्र में मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें सम्मानजनक तरीके से चुनाव में हिस्सेदारी मिले। महानगरपालिका के स्तर पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी से मिल रहे हैं एवं उन्हें सम्मानजनक हिस्सा देने की मांग उनसे कर रहे हैं। प्रत्येक महानगरपालिकाओं में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 7 से 10 सीट मांग रही है, वहीं मुंबई में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने 25 सीटों की डिमांड भेजी है।



बैठक में धांगेकर की 'नो एंट्री'

पुणे। पुणे नगर निगम चुनाव की लड़ाई शुरू हो चुकी है और पहले चरण में महागठबंधन के भीतर की कलह खुलकर सामने आ गई है। भाजपा और शिवसेना (शिंदे समूह) के बीच सीट बंटवारे पर हुई पहली महत्वपूर्ण बैठक में शिवसेना नेता और आक्रामक चेहरे रवींद्र धंगेकर को जानबूझकर दूर रखा गया। दरअसल पुणे में आयोजित इस बैठक में भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले, मंत्री चंद्रकांत पाटिल, सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले तथा शिवसेना मंत्री उदय सामंत और बापू शिवतारे उपस्थित थे। हालांकि, इस बात पर सभी की भौंहे तन गई हैं कि कस्बा पेठ में भाजपा के 40 साल पुराने गढ़ को ध्वस्त करने वाले धांगेकर को आमंत्रित नहीं किया गया था।

मिला पानी तब नेताजी ने बालों पर चलवाई कैची

मुंबई। नेताओं पर अक्सर वादाखिलाफी को आरोप लगाते हैं लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई से बीजेपी के विधायक राम कदम ने वादा करने तक बाल नहीं कटवाने का संकल्प लिया था। गुरुवार को उन्होंने अपने क्षेत्र के ऊपरी पहाड़ी इलाकों को पानी मिलने के बाद बाल कटवाए। राम कदम मुंबई बीजेपी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। वह पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। इस मौके पर राम कदम काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में पानी की आपूर्ति शुरू होने तक बाल न कटवाने का संकल्प लिया था। गुरुवार को यह वादा पूरा हुआ और उन्होंने अपने बाल कटवाए।



जेन जी

हम चाहते हैं कि हमारे वोट से ऐसा नेतृत्व चुना जाए जो युवा रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर गंभीर हो। सिर्फ वादे करने वाले नेता नहीं, बल्कि काम करने वाले चाहिए।



- मिताली मयेकर, मुंबई

मनपा चुनाव में हमारा मकसद सिर्फ पारंपरिक वोट नहीं देना है। हमें पारदर्शिता, साफ-सुथरी सड़कें, पानी और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं की प्राथमिकता वाले नेताओं को चुनना चाहिए।



- रिया सुर्वे, मुंबई

हमें भेजें
अगर आप भी अपने विचार हमें भेजना चाहते हैं तो **8356804318** इस नंबर पर व्हाट्सप्य करें।

विश्लेषण

मीरा-भाईदर महानगरपालिका

विनय दूबे | भाईदर

मीरा-भाईदर महानगरपालिका चुनाव में सत्ता के तीन प्रमुख दावेदार— शिवसेना (शिंदे) के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और कांग्रेस के पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन—मैदान में हैं। हालांकि वास्तविक मुकाबला भाजपा और शिवसेना के बीच ही होने के आसार हैं। तीन साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे इस चुनाव में 16 जनवरी को यह स्पष्ट होगा कि 8 लाख से अधिक मतदाताओं ने किस शहर की कमान सौंपी और कौन इस चुनावी रणभूमि का असली "रणवीर" बनकर उभरेगा।

तीन साल बाद चुनाव, सीमित प्रचार अवधि

मीरा-भाईदर मनपा चुनाव को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मात्र 9 दिनों का समय दिया है। इसके बावजूद चुनावी तैयारी के मामले में भाजपा फिलहाल अन्य दलों से आगे दिखाई दे रही है।

2017 के नतीजे और बदले हालात:

2017 के मनपा चुनाव में कुल 95 सीटों में भाजपा को 61, अविभाजित शिवसेना को 22 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली थीं। लेकिन समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां और समीकरण बदल चुके हैं, जिससे इस बार का चुनाव पहले से कहीं अधिक दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हो गया है।

भाजपा बनाम शिवसेना: असली मुकाबला

सत्ता हासिल करने की मुख्य लड़ाई भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता और शिवसेना (शिंदे) के प्रताप सरनाईक के बीच मानी जा रही है। भाजपा जहां मजबूत संगठन और जनाधार के साथ मैदान में है, वहीं प्रताप सरनाईक लगातार शिवसेना को मजबूती देने में जुटे हैं।

95 पार्षदों के लिए मुकाबला

मीरा-भाईदर महानगरपालिका के 24 प्रभागों में कुल 95 पार्षद चुने जाएंगे। इनमें से 48 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रभाग क्रमांक 1 से 23 तक चार सदस्यीय पैनल प्रणाली से चुनाव होंगे, जबकि भाईदर पश्चिम के उत्तम क्षेत्र में स्थित प्रभाग क्रमांक 24 में तीन सदस्यीय पैनल के अनुसार मतदान कराया जाएगा। पैनल प्रणाली और महिला आरक्षण के कारण राजनीतिक दलों के सामने टिकट वितरण एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।

शिवसेना के सामने बड़ी चुनौती

शिवसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने पारंपरिक और कठोर मतदाताओं को एकजुट करना है। यदि भाजपा और शिवसेना के बीच कोई युति नहीं होती है, तो इसका सीधा नुकसान शिवसेना को उठाना पड़ सकता है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है।

कांग्रेस की रणनीति और उम्मीदें

कांग्रेस पूर्व विधायक मुजफ्फर हुसैन के नेतृत्व में आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। पार्टी के सामने सवाल यह है कि क्या वह अपनी पारंपरिक वोट बैंक के सहारे 12 सीटें बचा पाएगी या फिर अपनी स्थिति में इजाफा कर सकेगी।

राजनीतिक विशेषज्ञों की राय

कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव के बाद मीरा-भाईदर की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। उनके अनुसार भाजपा और शिवसेना की युति की संभावना बेहद कम है और यदि युति होती भी है, तो इसका नुकसान अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को हो सकता है।

मतदाता और सीटों का गणित

मीरा-भाईदर में दो विधानसभा क्षेत्र—145 और 146 (ओवला-माजीवडा)—आते हैं। कुल मतदाता 8,19,151 हैं, जिनमें 4,33,053 पुरुष, 3,86,078 महिलाएं और 20 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। मनपा में कुल 24 प्रभाग और 95 सीटें हैं, जबकि सत्ता हासिल करने के लिए 48 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना जरूरी होगा।

24 प्रभाग, 95 पार्षद

कौन होगा मीरा-भाईदर का धुरंधर?



शिवसेना (शिंदे) के सामने दोहरी चुनौती

2017 के नतीजों के अनुसार भाईदर पश्चिम भाजपा का गढ़ रहा है, वहीं मीरा रोड और भाईदर पूर्व में भी भाजपा शिवसेना से अधिक

मजबूत रही है। 146 विधानसभा क्षेत्र से चार बार जीत चुके प्रताप सरनाईक के क्षेत्र में भी भाजपा के नगरसेवकों की संख्या अधिक रही

है। इस बार शिवसेना को शिवसेना (उबाटा) और मनसे से भी मुकाबला करना है, जिससे उसकी चुनौती और बढ़ गई है।

चुनावी कार्यक्रम

नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 से 30 दिसंबर 2025 तक चलेगी। नामांकन की जांच 31 दिसंबर को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है। चुनाव चिन्ह 3 जनवरी को वितरित होंगे, प्रचार 4 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी को समाप्त होगा। मतदान 15 जनवरी और मतगणना 16 जनवरी 2026 को घोषित किए जाएंगे।

भाजपा का आत्मविश्वास और रणनीति

भाजपा की ओर से 145 विधानसभा अध्यक्ष रवि व्यास ने दावा किया है कि शहर की जनता का भरोसा पार्टी के साथ है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। वहीं विधायक नरेंद्र मेहता ने कहा कि पार्टी का एकमात्र संकल्प शहर का विकास है और 21 दिसंबर को मीरा रोड के सेंट्रल पार्क में भव्य संकल्प सभा के साथ चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाएगी। भाजपा का दावा है कि इस बार भी शहर में "कमल" खिलेगा।

घाटकोपर पश्चिम

आयाराम-गयाराम से बदला समीकरण



धीरज सिंह | मुंबई

घाटकोपर पश्चिम विधानसभा के अंतर्गत आने वाला एन वार्ड से कुल 6 नगरसेवक चुने जाते हैं। इस बार आरक्षण के चलते 6 में से 5 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पूरे वार्ड में कुल 2,61,262 मतदाता हैं। 2017 के मनपा चुनाव में 6 में से 3 सीटें अविभाजित शिवसेना, 1 मनसे, जबकि भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक-एक सीट मिली थी। स्थानीय समीकरणों की बात करें तो मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। राजनीतिक हलकों में यह आकलन है कि घाटकोपर पश्चिम में अब भी शिवसेना (उबाटा) गुट का प्रभाव बना हुआ है। सामाजिक संरचना में सवर्ण, सामान्य



दलबदलुओं ने बदली चुनावी गणित

हाल के वर्षों में दलबदल ने वार्ड का राजनीतिक गणित बदल दिया है। एनसीपी (शरद पवार गुट) के पूर्व नगरसेवक हारुन खान और अविभाजित शिवसेना की पूर्व नगरसेविका अश्विनी दीपक हांडे शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गुट में शामिल हो चुकी हैं। वहीं मनसे की पूर्व नगरसेविका डॉ. अर्चना संजय भालेराव और वार्ड 123 से निर्दलीय विजेता स्नेहल मोरे शिवसेना (उबाटा) गुट में आ गई हैं। इन फेरबदल से इस बार परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं।

और दलित मराठा मतदाता बहुसंख्यक मुस्लिम मतदाताओं की भी निर्णायक हैं। इसके बाद उत्तर भारतीय और मौजूदगी है।

भाजपा का सीमित प्रभाव

घाटकोपर पश्चिम में भाजपा का प्रदर्शन ऐतिहासिक रूप से सीमित रहा है। 2017 में वार्ड 129 से भाजपा के सूर्यकांत गवली ने महज 215 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। इसके अलावा पार्टी कोई मजबूत प्रभाव नहीं छोड़ सकी है।

वार्ड 123: उबाटा गुट को बढ़त की उम्मीद

- वार्ड क्रमांक 123 में 2017 में निर्दलीय प्रत्याशी स्नेहल सुनील मोरे ने 9,322 मतों के साथ जीत दर्ज की थी, जो अब शिवसेना (उबाटा) में शामिल हो चुकी हैं। उनके मुकाबले अविभाजित शिवसेना की डॉ. भारतीय भावदाने को 8,597 वोट मिले थे। मौजूदा राजनीतिक स्थिति में स्नेहल मोरे का उबाटा गुट में जाना इस वार्ड में ठाकरे गुट की स्थिति को मजबूत करता नजर आ रहा है।

वार्ड 124: शिंदे गुट बनाम भाजपा

- वार्ड 124 में 2017 के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की ज्योति हारुन खान ने 6,686 वोट हासिल किए थे और अब वे शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गुट में हैं। उनके सामने

वार्ड 126: उबाटा गुट की मजबूत पकड़

- वार्ड क्रमांक 126 में मनसे की अर्चना संजय भालेराव ने 12,759 मतों के साथ प्रभावशाली जीत दर्ज की थी। वर्तमान में उनके शिवसेना (उबाटा) में शामिल होने से इस वार्ड में ठाकरे गुट की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। भाजपा की पूनम बारोटे, जिन्हें 6,089 वोट मिले थे, को इस बार कुटी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

वार्ड 127: ठाकरे गुट की परंपरागत ताकत

- वार्ड 127 में

वार्ड 128: शिंदे गुट को मिल सकती है बढ़त

वार्ड 128 में अविभाजित शिवसेना की अश्विनी दीपक हांडे ने 12,980 मतों के साथ जीत दर्ज की थी और अब वे शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गुट में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी शुभांगी शिर्के को 4,910 वोट मिले थे। इस वार्ड में शिंदे गुट की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही है।

क्या कहते हैं मतदाता? लोग क्या कहते हैं और उन्हें क्या चाहिए

- स्थानीय नागरिकों और मतदाताओं का कहना है कि विधानसभा क्षेत्र की लगभग 60 प्रतिशत आबादी स्लम में रहने के बावजूद उन्हें आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। भटवाड़ी, गांवदेवी, रामनगर, राहुल नगर, हनुमान नगर, पार्कसाइट, चिराग नगर, अमृतनगर और आंबेडकर नगर जैसे इलाकों में रहने वाले लोग खुद को लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हर चुनाव में विकास के वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं।
- निवासियों के अनुसार पहाड़ियों के किनारे सुरक्षा दीवारें नहीं होने से बारिश के दिनों में भूस्खलन का डर बना रहता है, फिर भी प्रशासन इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि जान जोखिम में डालकर रहना उनकी मजबूरी बन चुकी है, जबकि वर्षों से वे स्थायी सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं।
- पानी, शौचालय, सड़क, ट्रैफिक और सफाई जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर और पर्याप्त पौने का पानी नहीं मिलता, कई सार्वजनिक शौचालय तोड़ दिए गए हैं और उनका पुनर्निर्माण अधूरा पड़ा है। लोगों की मांग है कि सबसे पहले जलापूर्ति व्यवस्था सुधारी जाए, शौचालयों का तत्काल निर्माण पूरा किया जाए, सड़कों व ट्रैफिक की समस्या हल हो और नियमित साफ-सफाई के जरिए क्षेत्र को रहने लायक बनाया जाए।

आंकड़ों में इलेक्शन

मुस्लिम वोटर हैं 'मुंबादेवी' में प्रभावी

दक्षिण मुंबई की मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले प्रभागों में बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बेहद दिलचस्प हो गए हैं। कांग्रेस और महायुति के बीच यहां सीधा और कड़ा संघर्ष तय माना जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी (एसपी) और एआईएमआईएम की मौजूदगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। यदि उद्वेग टाकरे गुट और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं, तो मुकाबला महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच आमने-सामने का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बीएमसी चुनाव में इसी इलाके में विधानसभा चुनाव जैसे रुझान दोधुवां तक सीमित न रहकर दोहराए जाने की संभावना बन



सकती है। वहीं, प्रभाग की कुल पांच सीटों में से तीन पर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का प्रभाव दिख सकता है, जिससे मुकाबला दो धुवां तक सीमित न रहकर बहुकोणीय रूप ले सकता है।

कुल प्रभाग और प्रभावी पार्टियां:

- मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 प्रभाग हैं। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस और महायुति के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि समाजवादी पार्टी (एसपी) और मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) का असर 3 प्रभागों में देखा जा सकता है।
- पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े:
 - कांग्रेस को 5 में से 3 प्रभागों (213, 221, 223) में बढ़त मिली।
 - महायुति ने 2 प्रभाग (216, 220) में अग्रता बनाई।
 - मतदाता संरचना:
 - मुस्लिम मतदाता: लगभग 51%
 - अन्य प्रमुख समुदाय: मराठी, गुजराती-राजस्थानी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय
 - बीएमसी चुनाव में व्यापारिक और मध्यमवर्गीय इलाकों में महायुति को अधिक समर्थन
 - बीएमसी में पूर्व स्थिति:
 - कांग्रेस: 3 प्रभाग
 - बीजेपी: 2 प्रभाग

वॉर्ड आरक्षण का आंकड़ा:

- 213 - सामान्य
- 216 - ओबीसी महिला
- 220 - सामान्य महिला
- 221 - सामान्य
- 223 - ओबीसी

चुनावी चुनौती:

- कांग्रेस के लिए चुनौती: विधानसभा में मिली बड़ी जीत को बीएमसी में जीत में बदलना।
- महायुति और बीजेपी के लिए चुनौती: पुरानी सीटें बचाकर राजनीतिक पकड़ मजबूत करना।